● वर्ष-3
● अंक-69
रायपुर, रविवार
29 अक्टूबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› जिम करने वाले सितारों पर कंगना...

छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ करेंगे-राहुल

केजी (किंडरगार्टन) से पीजी (पोस्ट-ग्रेजुएशन) तक छात्रों के लिए सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा

भानुप्रतापपुर। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को वादा किया कि वह राज्य में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके झूठे वादों के लिए कटाक्ष करते हुए यह टिप्पणी की। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वे (भाजपा) किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते, वे केवल अडानी का कर्ज माफ कर सकते हैं। हमने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और हमने ऐसा किया। मैं एक बार फिर यह वादा कर रहा हूं कि हम फिर से छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस राज्य में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। आज कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी कांकेर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा।

गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने हर बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगा। मैं जो कहता हूं, वह करता हूं। भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पार्टी किसानों का पैसा अडाणी समूह को देती है और दावा किया कि वह दो-तीन

उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि आप किसी भी सरकार को देखें, तो राज्य या देश के सबसे अमीर लोगों को लाभ पहुंचाने या देश या राज्य के सबसे गरीब लोगों की मदद करने के तरीके हैं। जहां हमारी सरकार किसानों, मजदूरों और गरीबों की मदद करती है, वहीं भाजपा सरकार केवल बड़ी-बड़ी बातें करती है लेकिन अंत में अडानी की मदद करते हैं।

छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा करने के अलावा, गांधी ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं जिसे हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी (किंडरगार्टन) से पीजी (पोस्ट-ग्रेजुएशन) तक छात्रों के लिए सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्हें एक भी पैसा नहीं देना होगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता बरकरार रखती है तो तेंदू पत्ता संग्राहकों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये दिए जाएंगे।

उद्योगपतियों की मदद करने का लगाया आरोप

राहल ने कहा कि आज देश में खदान, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, अडानी जी को दिए जाते हैं। किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वह कानून अडानी जी की मदद करते हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में सेब का पूरा व्यापार अडानी जी के हाथ में है। जम्मू-कश्मीर में भी सेब का पूरा व्यापार अडानी जी के पास है, वे जो भी करते हैं देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करते हैं।

अपने संबोधन में राहुल ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने दो घंटे में वो कर दिखाया जो भाजपा ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। 26 लाख किसानों को 23 लाख करोड़ रुपए दिये गए, 5 लाख मजदूरों को 7000 रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हमने छत्तीसगढ़ से 2-3 बड़े वादे किए थे। किसानों की फसलों का सही दाम, किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ होगा। जब हम ये वादे कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा था- ये वादे पूरे नहीं होंगे। लेकिन हमने सरकार बनते ही उस काम को 2 घंटे में पूरा कर दिखाया था।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका- सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, दूसरा तरीका- गरीब लोगों की मदद करो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों और बेरोजगारों की मदद करती है। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की मदद करती है। वहीं, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात भूल जाइए, वे (बीजेपी) तीन कृषि कानून लेकर आए। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया और विरोध के दौरान 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। वे हमेशा किसानों के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई गाथा नहीं, जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं।

राम मंदिर को लटका-अटका-भटका रही थी कांग्रेसः शाह

छिंदवाड़ा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कांग्रेस नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे थे। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मध्य प्रदेश की जनता से ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने अयोध्या में श्रीराम मंदिर का भूमि पूजन किया। 22 जनवरी, 2023 को वहां पर रामलला की स्थापना होने वाली है।

- कांग्रेस को कभी कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता, इनकी जड़ें इटली से हैं

शाह ने कहा कि आज पूरी ?दुनिया में भारत के विकास की चर्चा है, भारत का गौरवगान हो रहा है। बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत के परचम को पूरी दुनिया में लहराया है। इस सबके बावजूद कांग्रेस को कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। ये भाई-बहन चुनावी राज्यों में घूम-घूम कर पूछ रहे हैं, क्या हुआ है? अरे भाई... आपको समझ नहीं आएगा, जिनके मूल भारत में लगे हैं उन्हें समझ आएगा। जिनके मूल इटली में हैं उन्हें समझ नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी कल्याण का भाजपा का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अटल जी ने आजादी के कई वर्षों बाद सबसे पहले आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, जनजाति आयोग का गठन किया और मोदी जी ने 23 से अधिक जनजातियों को आदिवासियों की सूची में जोड़ा।

भाजपा नेता ने कहा कि 2013-14 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और देश में आदिवासी कल्याण के लिए कांग्रेस 29 हजार करोड़ रुपया खर्च करती थी। अब मोदी सरकार आदिवासी कल्याण के लिए 1 लाख 38 हजार करोड़ रुपया खर्च करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 परिवारों का बोलबाला है। गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय परिवार। जहां तीन तिगड़ा होता है, वहां काम बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कभी कुछ भी सकारात्मक नजर नहीं आता, ये भाई-बहन पूरे देश में घूमते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि क्या हुआ...खैर इन्हें समझ नहीं आएगा।

जरांगे ने कहा कि आंदोलन का तीसरा चरण 31 अक्टूबर को शुरू होगा और 30 अक्टूबर को इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। उन्होंने दोहराया कि सत्तारूढ़ दलों के साथ-साथ विपक्ष के राजनीतिक नेताओं को गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हेमंत सोरेन को सिर्फ वोट की चिंता है: नड्डा

रांची। नड्डा ने कहा कि जब मैं हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमें ध्यान आता है कि इन्होंने आदिवासियों के बारे में चर्चा की, उनके नाम पर वोट मांगे और जितना नुकसान आदिवासियों और उनके हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड के दौरे पर रहे। रांची में उन्होंने संकल्प यात्रा 2023 के समापन पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इसल दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये फ़रेबियों की सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है। ये सरकार अत्यंत भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे श्वष्ठ पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जहां शराब माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया हर किस्म के माफिया दनदना रहे हैं।

नड्डा ने कहा कि जब मैं हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमें ध्यान आता है कि इन्होंने आदिवासियों के बारे में चर्चा की, उनके नाम पर वोट मांगे और जितना नुकसान आदिवासियों और उनके हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने

कहा कि वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण को मौन रहकर देखना अपने आप में बताता है कि हमारे भाईयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए लेकिन हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वो वोट के लिए हर कुछ करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि पर संकल्प यात्रा के समापन में आप लोगों के साथ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं वह बताता है, आपने तय ?कर लिया है कि अगली बार यहां पर कमल खिलाना है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम जानते हैं कि आदिवासियों की चर्चा बहुत लोगों ने की। आदिवासियों के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कीं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पीएम मोदी ने स्थापित किया। उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण पर आंख मूंद ली, ये बताता है कि हेमंत सोरेन को आदिवासियों की संस्कृति की नहीं सिर्फ वोट की चिंता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब छ्रूरू के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं।

जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसी सरकार जो तुष्टिकरण से युक्त हो, भ्रष्टाचार से युक्त हो, अनाचार से युक्त हो, उस सरकार को हम नहीं रहने देंगे।

प्रमुख समाचार

भाजपा विपक्ष को डरा रही, उन्हें भी भुगतना होगा-खरगे

नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में इस बाबत सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच, राजस्थान में ईडी

की हालिया छापेमारी को लेकर विवाद तेज हो गया है। विपक्षी पार्टियां पहले से ही मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं। अब इस ताजा कार्रवाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन छापेमारी से नहीं डरेगी और एक दिन भाजपा को भी इसे झेलना पड़ेगा। खरगे ने आगे कहा कि वे गहलोत के चुनाव को बर्बाद करना चाहते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को डराना चाहते हैं। वह ऐसा हमेशा करते हैं लेकिन हम इससे नहीं डरेंगे और इसका मजबूती से सामना करेंगे। वह जो भी कर रहे हैं, वह सही नहीं है। हम 50 सालों से राजनीति कर रहे हैं लेकिन चुनाव के दौरान कभी भी ईडी, सीबीआई की छापेमारी नहीं हुई।इससे पहले, शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा गुंडागर्दी कर रही है।

मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर 30 को फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। सिसौदिया पर वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन

निदेशालय (ईडी) द्वारा घोटालों से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मुकदमा चल रहा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मामलों और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं के लिए धन के आवंटन की सुविधा के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह फरवरी से न्यायिक हिरासत में हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच सोमवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। 17 अक्टूबर को मामले पर आखिरी सुनवाई के दौरान, केंद्र के खिलाफ सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के साथ अंतिम बहस समाप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना फैसला टाल दिया था। 5 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों से कड़े सवाल पूछे थे।

कर्नाटक सियासत- ढाई साल बाद राज्य में बदलेगा सीएम!

बेंगलूरू। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर इन दिनों चर्चाएं तेज हैं। दरअसल, कांग्रेस के मांड्या से विधायक रविकुमार गौड़ा ने दावा किया है कि मौजूदा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल

के बाद उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद से राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के हलकों में खलबली मच गई है। इसके साथ ही शुक्रवार रात गृह मंत्री जी परमेश्वर के घर पर हुई एक बैठक ने भी इन अटकलों को हवा दे दी है। कांग्रेस विधायक के सीएम बदलने वाले बयान से कर्नाटक में हड़कंप मचा हुआ है। उनके बयान के बाद पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वहीं, कुछ अन्य नेताओं का कहना है कि सीएम पद को लेकर कोई भी निर्णय लेना आलाकमान का काम है। इसके अलावा, शुक्रवार रात गृह मंत्री जी परमेश्वर के आवास पर एक रात्रिभोज बैठक ने भी राज्य में ढाई साल बाद सीएम बदलने की अटकलों को हवा दे दी है। दरअसल, इस बैठक में सीएम सिद्धारमैया, समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीह जराकीहोली शामिल हुए थे।

बीजेपी के मुकाबले के लिए मजबूत नहीं विपक्ष का गठबंधन

नई दिल्ली। गाजा पर इजरायल की बमबारी और बढ़ती फिलिस्तीनी मौतों का असर उर्दू प्रेस के दिमाग पर जारी रहा। अगले महीने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को भी इसके पहले पन्नों और संपादकीय में महत्वपूर्ण जगह मिली। जैसे-जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी तीन प्रमुख उर्दू अखबारों, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, इंकलाब और सियासत ने भाजपा और विपक्षी गठबंधन दोनों के अभियानों की व्यापक कवरेज की है। इंकलाब के एक संपादकीय में विपक्षी गुट की आलोचना की गई है, खासकर मध्य प्रदेश में टिकट वितरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच मतभेद के आलोक में को लेकर। इज इंडिया स्टिल ऑन होल्ड शीर्षक से 27 अक्टूबर के संपादकीय में विपक्षी गठबंधन को चेतावनी देने की कोशिश की गई कि वह उतना मजबूत नहीं है जितना अगले साल के संसदीय चुनाव के दौरान भाजपा का मुकाबला करने के लिए होना चाहिए। इसकी बैठकें नहीं हो रही हैं। क्या इसकी सभी गतिविधियां गुप्त हैं और (यदि हां) तो क्या वे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद सामने आ जाएंगी।

पीएफआई मामले में आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र

नई दिल्ली/पटना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बिहार में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की कथित गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में प्रमुख आरोपी अनवर राशिद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर का निवासी राशिद उन सत्रह आरोपियों में शामिल है, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पिछले साल 12 जुलाई को फुलवारी शरीफ थाने में 26 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एजेंसी ने दस दिन बाद मामले को अपने हाथ में लिया और सात जनवरी, तीन अगस्त और एक सितंबर को 13 संदिग्धों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। उन्होंने कहा, जांच में पता चला है कि राशिद पूर्व में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी का सदस्य था। सिमी पर प्रतिबंध के बाद वह %वहदत-ए-इस्लामी, हिंद% समूह के साथ जुड़ गया, जबकि सिमी की चरमपंथी, गैरकानूनी और हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देना जारी रखा। उन्होंने कहा, सिमी पर प्रतिबंध के बाद इसके सदस्यों ने अपना सब कुछ बदल दिया।

गोबर से बना सकते हैं सोना, खत्म होगी आवारा पशुओं की समस्या

अमित शर्मा

जब से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोवंश की हत्या पर सख्ती बरती है, राज्य में गोवंश की हत्या रुक गई है। लेकिन इसका एक नकारात्मक परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि अब राज्य में जगह-जगह पर आवारा पशु दिखाई पड़ रहे हैं। ये दिन में सड़क-चौराहों पर ट्रैफिक समस्या का कारण बने रहते हैं, तो रात के समय ये किसानों की फसल चर जाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। लंबी बहस के बाद भी अब तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है।

लेकिन इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादा किया है कि यदि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में वापस आ जाएगी, तो वह किसानों से दो रुपये किलो की दर से गाय का गोबर खरीदेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पहले ही छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों से गाय का गोबर इसी दर पर खरीद रही है। सरकार इस गोबर का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाकर उसको कृषि में लगाने की योजना बना रही है। इससे रासायनिक खादों की आवश्यकता कम हो सकेगी, वहीं लोगों को जैविक खेती से बेहतर उत्पाद मिल सकेंगे।

पशुधन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई हवा-हवाई बात नहीं है। इसमें जमीनी सच्चाई है कि यदि गाय दूध देना बंद भी कर दे, उसके बाद भी उसके गोबर से इतनी कमाई की जा

सकती है कि उससे न केवल गाय को पालने का खर्च निकल सकता है, बल्कि इससे किसान परिवार को बड़ी आर्थिक मदद भी मिल सकती है।

गुजरात के कच्छ क्षेत्र के गोपालक मेघजी हिरानी ने अमर उजाला को बताया कि वे नीलकंठ गोविज्ञान केंद्र के नाम से एक गोशाला चलाते हैं। इस गोशाला में इस समय 48 गायें हैं। दूध देने वाली एक गाय को चारा खिलाने का एक दिन का खर्च लगभग 60 रुपये आता है, तो दूध देने वाली गाय के चारे पर 170 रुपये का खर्च आता है। लेकिन किसी भी गाय के गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाकर एक साल में एक लाख रुपये तक की कमाई की जा सकती है। इसमें सभी खर्च काट कर भी एक गाय से लगभग 40 हजार रुपये तक की कमाई हर साल की जा सकती है।

एक गाय से 40 हजार की कमाई

मेघजी हिरानी ने बताया कि उनके कच्छ क्षेत्र में ही इस समय लगभग 102 छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जो गाय के गोबर से दीपक, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, शुभ-लाभ के प्रतीक चिन्ह, छोटे-छोटे घर और खिलौने जैसे कुछ उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। खुदरा बाजार में इनकी कीमत दस रुपये से लेकर 200 रुपये के करीब तक है। गोबर विज्ञान को सीखकर कोई भी व्यक्ति इसे स्वरोजगार का साधन बना सकता है। इससे वह एक गाय से हर साल लगभग 40 हजार रुपये तक की कमाई कर सकता है।

कच्छ क्षेत्र में इस तकनीक को सिखाने के लिए कई केंद्र चल रहे हैं। इसमें दो से तीन दिन का सामान्य कोर्स करके कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार शुरू कर सकता है। छोटे स्तर पर काम करना शुरू करने में कोई पूंजी नहीं लगानी पड़ती है। पांच-दस हजार रुपये में उत्पादन में लगने वाली सुगंधी जैसी अन्य चीजें खरीदी जा सकती हैं। लेकिन काम में ज्यादा वृद्धि होने पर मशीनें लगाई जा सकती हैं। इसमें कुछ लागत लग सकती है, लेकिन इससे कमाई में भी बहुत वृद्धि होने की संभावना होती है।

बघेल सरकार की योजना

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार इस समय किसानों से दो रुपये किलो की दर से गाय का गोबर खरीद रही है। सरकार ने इसे %छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना% का नाम दिया है। इस योजना को 20 जुलाई 2020 को शुरू किया गया था। कोई भी किसान एक फॉर्म पर आवश्यक सूचना देकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। गोबर खरीद की राशि सीधे किसानों के खाते में भेज दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत जून 2023 तक 488 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में सांड़ों की समस्या

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ विशेष पशुओं की कटाई पर रोक लगा चुकी है। सरकार ने ये कदम गौवंश की कटाई को रोकने के लिए उठाया था। इससे गौ तस्करों के द्वारा गोवंश की अवैध कटाई पर लगाम लगाई जा चुकी है। लेकिन इसका नकारात्मक असर यह हुआ है कि अब जगह-जगह पर आवारा पशु घूमते रहते हैं। सड़कों-चौराहों पर उनके घूमने से ट्रैफिक की समस्या पैदा हो रही है, तो ये पशु रात को किसानों की फसलें चर जा रहे हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।

छत्तीसगढ़ में पहली बार मसीही समाज भी चुनावी मैदान में

कांकेर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए 7 नवंबर को वोटिंग है। इस बार बस्तर संभाग का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में सामाजिक संगठन भी इस बार राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतार रहे हैं। आदिवासी समाज का सामाजिक संगठन सर्व आदिवासी समाज ने हमर राज पार्टी बनाई है और चुनावी मैदान में है। वहीं छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार मसीही समाज भी चुनावी मैदान में है। मसीही समाज के कुछ प्रमुख लोगों ने सर्व आदि दल के नाम से चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं।

सर्व आदि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने मीडिया को बताया कि बस्तर में फिलहाल 9 प्रत्याशी उतारे हैं। सर्व आदि दल ने बस्तर के जगदलपुर, बस्तर, कोंडागांव, केशकाल, चित्रकूट, अन्तागढ़, कांकेर में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, हालांकि लक्ष्य बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का था। उन्होंने कहा हमें समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। तीन सीट में पैसे की कमी की वजह से हम प्रत्याशी नहीं उतार पाए, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। हम अपनी जेब से ही चंदा जुटा कर चुनाव लड़ रहे हैं।

अरुण पन्नालाल कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मसीही समाज के लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे 4 पादरियों की हत्या हुई है। पुलिस ने भी हमारा सहयोग नहीं किया। बस्तर क्षेत्र में मसीही समाज की लगभग 200 लाशों को खोद कर बाहर निकाला गया। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस खुद सक्रिय होकर हंगामा करती है। बहुत सारे मामलों में हमने न्यायालय के

दरवाजे भी खटखटाए हैं। तकरीबन 400 केस हुए हैं, जिसमें मसीही समाज के लोगों को मारा पीटा गया है। हमें चोट खाने या मार खाने से उतनी पीड़ा नहीं है, जितनी पुलिस की निष्क्रियता से पीड़ा है।

अरुण पन्नालाल ने कहा हमें राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है। ना हमें कोई पावर पॉलिटिक्स में जाना है। पहली बार छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक आयोग में हमारा सदस्य नहीं है, बाकि किसी भी आयोग में हमारा कोई सदस्य नहीं है।

अरुण पन्नालाल कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को गौ आयोग का सदस्य बनाया गया। क्या ईसाई समाज गौ की सेवा करेगा, इसलिए हमारे समाज के लोग उसको जॉइन ही नहीं किए। अब हम अपनी बात करेंगे तो किससे करेंगे? मुख्यमंत्री भी हमारी बात नहीं सुनते बल्कि उनका बयान आता है आप 2% हैं, आपकी क्यों सुनें?

अरुण पन्नालाल का कहना है कि भाजपा धर्मांतरण का मुद्दा उठाती है, लेकिन कांग्रेस को फैक्ट्स और फिगर्स पर बात करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरा कुछ भी हो मंशा कुछ और रहती है। आज कांग्रेस पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व वाली है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम सेकुलरिज्म है, अपनी आर्डियोलॉजी बताती है लेकिन आप काम कर रहे हो राइट विंग का।यह विराधाभास और भ्रम की स्थिति में ईसाई समाज है। कांग्रेस यहां सोचती है कि हम इन्हें प्रताड़ित भी करते रहें और सेकुलरिज्म भी चलाते रहें।

उन्होंने कहा आज हर आदमी पढ़ा लिखा है। ईसाई समाज सब समझता है। हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, इसीलिए हमने पार्टी बनाई है और चुनावी मैदान में हैं।

अरुण पन्नालाल का कहना है कि अभी सर्व आदि दल केजी 1 में है। पहली बार 75 साल में ईसाई समाज पॉलिटिक्स में उतरा है। पहले दिन ही बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगेगा, यह संभव नहीं है, वैसे ही हम अभी पॉलिटिक्स में पैदा हुए हैं।

उन्होंने कहा हम अभी सामाजिक संरक्षण में ही हैं। इससे जब आगे बढ़ेंगे, तब जरूरी दूसरे समाज के साथ जाएंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि बाकी समाज के लोग भी हमसे संपर्क कर रहे हैं। एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अरुण पन्नालाल का यह भी कहना है कि अभी सर्व आदि दल अपने समाज को संगठित कर अपना सामाजिक वोट बैंक बना रहा है। इसके बाद दूसरे समाज का समर्थन मांगा जाएगा। सर्व आदि दल की आइडियोलॉजी स्पष्ट है। हम सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं। सबको समानता से देखते हैं।

आखिर कांग्रेसी किस मकसद से खरीद रहे नामांकन फार्म

जांजगीर चांपा जिले के दो पूर्व विधायकों ने लिया नामांकन फार्म

जांजगीर चांपा। जिले की तीनों विधानसभा सीट अकलतरा, जांजगीर चांपा और पामगढ़ विधानसभा सीट से प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आ रही है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों से 17 कांग्रेस नेताओं ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। इसमें पूर्व विधायक भी शामिल है। अब तक कांग्रेस, बीजेपी, बसपा और आप पार्टी के साथ निर्दलीय 67 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किया है।

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने राघवेन्द्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। जिसके बाद पूर्व विधायक चुन्नी लाल साहू ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक द्वारा नामांकन फार्म भरना किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है।

जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 34 से मोतीलाल देवांगन, रामकुमार साहू, व्यास कश्यप, ज्योति सिंह, बीना साहू ने नामांकन फार्म खरीदा है। मोती लाल देवांगन ने जांजगीर चांपा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट की दावेदारी की थी लेकिन पार्टी ने व्यास कश्यप को प्रत्याशी घोषित कर दिया। व्यास कश्यप ने अपना पहला सेट नामांकन भी भर दिया है, इसके बाद भी प्रत्याशी बदलने की संभावना को देखते हुए तैयारी करने की भी चर्चा चल रही है।

पामगढ़ विधानसभा सीट पर भी समीकरण सही नहीं दिख रहे हैं। गोरे लाल बर्मन पामगढ़ विधानसभा से दो बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और इस बार भी कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद में थे लेकिन कांग्रेस ने शेष राज हरबंश को टिकट दे दिया। जिसके बाद गोले लाल ने रायपुर से लेकर दिल्ली तक पार्टी के फैसले का विरोध जताया। इसके बाद जेसीसीजे में शामिल होकर पामगढ़ सीट से नामांकन पत्र लिया।कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद से जांजगीर चांपा जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के पदाधिकारियों में असंतोष की भावना सामने दिखने लगी। जिसका परिणाम कुछ लोग पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी में चले गए और जो बचे है उनमे भी अब तक प्रत्याशी बदलने की संभावना बनी हुई है।

छत्तीसगढ़ में कम बारिश से किसानों को मिला कर्जमाफी का फायदा?

सरगुजा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भी कर्जमाफी की घोषणा की हैं। इस घोषणा का फायदा कांग्रेस को चुनाव में कितना मिलेगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि किसानों का कर्ज कुछ हद तक कम होगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मीडिया को बताया कि किसानों से बात करने के दौरान उन्होंने इस साल बारिश नहीं होने के कारण सूखे पर चिंता जताई। जिसके बाद ये फैसला लिया गया।

टीएस सिंहदेव ने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी बारिश सामान्य रही। खासकर सरगुजा संभाग के कई इलाकों में सूखे की स्थिति बनी। चुनाव प्रचार के दौरान गांव के किसानों ने बारिश नहीं होने से फसल बर्बाद होने के बारे में बताया। जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की एक बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि साल 2018 की तरह इस साल भी किसानों का कर्जमाफ कर उन्हें राहत दी जाए।

बता दें कि इस साल छत्तीसगढ़ में औसत से कम बारिश हुई। 1 जून से 30

सितम्बर तक प्रदेश में 1142.1 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन सिर्फ 1061.3 मिलीमीटर बारिश हुई हैं। सरगुजा संभाग की बात करें तो यहां काफी कम बारिश हुई हैं। सरगुजा संभाग में जून से सितंबर तक 1223.2 मिलीमीटर बारिश होनी थी लेकिन जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 545.6 मिलीमीटर बारिश हुई। सरगुजा संभाग में सूरजपुर और जशपुर में सबसे कम बारिश हुई।

छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियों को लेकर सिंहदेव ने बताया कि ज्वॉइंट लीडरशिप में कांग्रेस काम कर रही हैं। जिसको जैसा समय मिल रहा है वो अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। अपनी विधानसभा में भी समय दे रहे हैं। पार्टी के लिये जितना बेहतर हो सके सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा साल 2018 में जनता ने भरोसा जताया, हमें काम करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और काम करना चाह रहे हैं। इसी भरोसे के साथ जनता से वोट मांग रहे हैं।

टिकट ना मिलने से नाराज और कांग्रेस के बागियों के लिए टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब किसी एक को टिकट मिलता है तो बाकी नाराज हो जाते हैं। उनको समझाना पड़ता है कि संगठन के माध्यम से जनता के प्रति उनकी क्या जवाबदारी है। उन्हें बताया होता है कि हमने अपने लिए टिकट नही मांगा बल्कि पार्टी के लिए टिकट मांगा। संगठन में किसको क्या जिम्मेदारी देना है ये पार्टी तय करती है। सभी को उस दायरे में रहकर काम करना चाहिये।

अंबिकापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल के साथ सीधी टक्कर को लेकर सिंहदेव ने कहा कि हम लोग सब सरगुजा के परिवार के सदस्य हैं। चुनाव में आपसी दुराव नहीं होना चाहिये, ना ही ऐसा है। राजनीतिक दल से जुड़ कर चुनाव लड़ना होता है। हर दल की अपनी विचारधारा है, उसके अनुसार हमें करना होता है, लेकिन संबंधों में दुराव नहीं होना चाहिये।

बस्तर में मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी लाखों जवानों की सुरक्षा के साये में होगी वोटिंग

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग बेहद संवेदनशील है। नक्सलियों के कारण बस्तर संभाग के कई जगहों पर मतदान कराना चुनौती भरा होता है।नक्सली संगठन सभी तरह के राजनीतिक चुनाव का बहिष्कार करते हैं। बस्तर संभाग का सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर जैसे जिलों में नक्सलियों की मौजूदगी बनी रहती है। इन जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नक्सली छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं।

बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाको में किसी भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना एक बड़ा टास्क है। सुरक्षाबल के जवानों और निर्वाचन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए चुनाव के दौरान शांति बनाए रखना पहली चुनौती होती है।शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए बस्तर संभाग में जवानों ने कमर कस ली है। सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग के साथ नक्सल विरोधी अभियान भी तेज कर दिया गया है। बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में 1 लाख से अधिक जवानों के सुरक्षा के साये में 2023 का विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा।

बस्तर संभाग में स्थानीय युवक युवतियों को लेकर नक्सली मोर्चे पर बस्तर फाइटर की तैनाती कर दी गई है। जिसमें बड़ी संख्या में महिला कमांडो भी शामिल हैं। इसके अलावा पहले से ही

डीआरजी, दंतेश्वरी फाइटर्स, दुर्गा फाइटर्स, जिला बल में मौजूद महिला बल की संख्या काफी है। महिला सुरक्षा कर्मी भी मतदान केंद्रों में सुरक्षा देंगी। एक तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। वहीं बस्तर में चुनाव संपन्न करने के लिए महिला कमांडो की तैनाती मतदान केंद्रों में होगी। जो काफी सराहनीय है।बस्तर आईजी सुन्दराज पी। ने कहा कि आगामी 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान बस्तर संभाग में संपन्न किया जाएगा। इस प्रक्रिया को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी तैयारी की गई है।

छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के 35 मतदान केंद्रों की सुरक्षा पूरी तरह से बस्तर फाइटर्स की महिला कमांडो करेंगी। एक बूथ ट्रांसजेंडर पुलिस की निगरानी में होगा। बस्तर संभाग के सात में से छह जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। आपको बता दें कि संभाग में 9.9 लाख पुरुषों की तुलना में 10.4 लाख महिला मतदाता हैं।

आईजी बस्तर सुंदरराज पी ने कहा पहले से ही बस्तर पुलिस के पास छ्रन्न, एसटीएफ, कोबरा, जिला बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ,आईटीबीपी के जवान तैनात है। इसके अतिरिक्त बाहर से भी चुनाव आयोग के माध्यम से अतिरिक्त बल प्राप्त हुआ है। इन सभी सुरक्षाबल के जवानों को आवश्यक इलाकों में तैनात किया गया है। और जिन इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। वहां सुरक्षाबल के जवानों की संख्या को बढ़ाकर और तेजी से ऑपरेशन तेज कर दी गई है।

सीमावर्ती इलाकों में भी जवान तैनात हैं। इसके लिए पहले से ही होमवर्क किया गया है। ताकि सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी हो सके। और चुनाव का कार्य सुरक्षित रीति से संपन्न हो सके। बिना किसी वारदात के संपन्न किया जा सके। इसके साथ ही बस्तर आईजी जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य से लगे सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत करके सुरक्षा के इंतजाम को तगड़ा किया गया है।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

नक्सलियों ने जेसीबी और टिप्पर में लगाई आग

बीजापुर। बीजापुर में चुनाव से पहले नक्सलियों ने एक बार फिर जिले में उत्पात मचाया है। शुक्रवार की रात मिरतुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने थाने से कुछ दूर पर खड़ी गाड़ियों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात नक्सलियों ने मिरतुर थाना से कुछ दूर खड़ी एक जेसीबी व एक टिप्पर को आग के हवाले कर दिया। बताया गया है कि मिरतुर से गंगालूर तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। ऐसे में ठेकेदार निर्माण का काम खत्म करने के बाद मिरतुर थाने के पास गाड़ियों को खड़ी कर देता हैं। शुक्रवार की रात थाने से कुछ दूर पर खड़ी वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया गया है कि यह घटना रात 11.30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने वहां आसपास पर्चे भी फेंके है। पर्चे में नक्सलियों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात लिखी है। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को सबक सिखाने की बात कही है।

टिकट नहीं मिलने पर योगेश ने खरीदा नामांकन फार्म

बेमेतरा। सात अक्टूबर को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के पूर्व नेता योगेश तिवारी ने रायपुर के रावणभाठा मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा में शामिल हुए थे। वे बेमेतरा से विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन, भाजपा ने ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपेश साहू को बेमेतरा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज योगेश तिवारी ने शुक्रवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन फॉर्म खरीदा है। उन्होंने कहा कि यहां वरिष्ठ नेता नहीं चाहते कि यहां से भाजपा जीते। हमें बैठकों और पार्टी के कार्यक्रम में तवज्जों नहीं दी जा रही है। भाजपा के उम्मीदवार की हैसियत से नामांकन लिया है। हालांकि वे आने वाले दिनों में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसे लेकर अपने कार्यकर्ताओं से मशवरा ले रहे हैं। वहीं, बेमेतरा जिले की तीनों विधानसभा साजा, नवागढ़ व बेमेतरा के लिए अब तक 55 फार्म बिक चुके हैं। 27 अक्टूबर को जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र के पांच उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र फॉर्म खरीदा है।

रामानुजगंज से आप ने नीलम ठाकुर को बनाया प्रत्याशी

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेसीसीजे और आम आदमी पार्टी लगातार उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को प्रत्याशियों की पांचवीं लिस्ट जारी की। इस बार पार्टी ने 12 प्रत्याशियों की घोषणा की है। प्रदेश की हाईप्रोफाइल रामानुजगंज विधानसभा सीट से नीलम ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है। बलरामपुर जिले की सामरी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट में देव गणेश टेकाम को टिकट दिया है। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कामेश्वर नगर की रहने वाली नीलम ठाकुर आप पार्टी में सक्रिय भूमिका में हैं। वर्तमान में आम आदमी पार्टी की जिला सचिव के पद पर हैं। बलरामपुर जिले की सामरी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने देव गणेश टेकाम को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने सामरी से उद्देशवरी को उतारा है। बलरामपुर जिले में आम आदमी पार्टी लंबे समय से तीसरी ताकत बनने की कोशिश में जुटी हुई है।

इस चुनाव में दिव्यांग और बुजुर्ग घर से डाल सकेंगे वोट

कोरबा। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए इस बार एक अहम फैसला लिया है। आगामी विधानसभा चुनावों में 80 साल या इससे से ज्यादा उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान (वोट फ्रॉम होम) की सुविधा दी है। छत्तीसगढ़ में ऐसे बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 2 लाख से अधिक है। जबकि 40 फ़ीसदी या इससे अधिक दिव्यांग मतदाताओं की भी कमी नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा वोट फ्रॉम होम की सुविधा देने के रचनात्मक फैसले का लाभ बुजुर्गों को मिलेगा। दिव्यांग भी बिना परेशानी घर से वोट डाल सकेंगे। इसके लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। दुजुर्ग और दिव्यांगों को अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को इसकी जानकारी देनी होगी। जिसके बाद अधिकारी ऐसे मतदाताओं तक पहुंचेंगे। वोट फ्रॉम होम के लिए फार्म 12डी सबसे महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को बीएलओ से यह फार्म प्राप्त करना होगा। मतदाता बीएलओ से स्वयं संपर्क कर सकते हैं।

प्रशासन ने झूठी खबर का आरोप लगाकर 4 पत्रकारों को जारी किया नोटिस

बीजापुर। जिले में नक्सली मुठभेड़ में इसी इलाके के इनामी कमांडर नक्सली नागेश पदम के मारे जाने के बाद नक्सली संगठन ने गुरूवार 26 अक्टूबर को बीजापुर बंद बुलाया, जिसका अच्छा खासा असर देखने को मिला, सभी दुकानें बंद रहे, आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। इसके एक दिन पूर्व 25 अक्टूबर को नक्सलियों ने जम कर उत्पात मचाया, 25 अक्टूबर को हुए नक्सली वारदात को लेकर स्थानीय पत्रकारों ने वाट्सअप पर नक्सलियों द्वारा आगजनी, गोलीबारी, विस्फोट कर मार्ग बाधित करने की जानकारी साझा करने पर जिला प्रशासन के अनुविभागिय दंड़ाधिकारी ने नक्सलियों द्वारा विस्फोट की वारदात एवं मार्ग के बाधित होने का खंडन करते हुए झूठी खबर वाट्सअप में प्रसारित करने का आरोप लगाकर स्थानी पत्रकारों ईश्वर सोनी, मुकेश चंद्राकर, एरोला रामचंद्रम एवं विशाल कुमार गोमांस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

निर्वाचन आयोग ने 7 भवन, 5 स्थल व 20 नाम परिवर्तन प्रस्ताव का किया अनुमोदन

जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 केतहत बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के भवन, स्थल और नाम परिवर्तन के प्रस्तावों को निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए जिले से सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के 7 भवन परिवर्तन, 05 स्थल परिवर्तन और 20 नाम परिवर्तन के साथ ही आंशिक नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र (बस्तर जिले के अंतर्गत) के 06 नाम परिवर्तन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तावित किया गया था, जिसका अनुमोदन कर दिया है।

निर्वाचन आयोग के अनुमोदन उपरांत भवन परिवर्तन में बस्तर-85 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक-169 तुंगापाल को पूर्व माध्यमिक शाला तुंगपाल, मतदान केंद्र क्रमांक -212 बेलगांव को माध्यमिक शाला बेलगाँव, जगदलपुर-86 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक-58 कुम्हली को माध्यमिक शाला कुम्हली, मतदान केंद्र क्रमांक-210 मांझीगुड़ा को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मांझीगुड़ा, मतदान केंद्र क्रमांक-232 मंगनार को हायर सेकंडरी स्कूल मंगनार नेगानार, मतदान केंद्र क्रमांक-235 तीरथगढ़ को शासकीय हाई स्कूल तीरथगढ़ और चित्रकोट-87 विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक-104 कोरंगाली को उच्च प्राथमिक शाला कोरंगाली किया गया है।

इसी प्रकार मतदान केंद्र के स्थल परिवर्तन में विधानसभा क्षेत्र-85 बस्तर के मतदान केंद्र क्रमांक-172 मसगांव का पूर्व माध्यमिक शाला सरगीपाल, विधानसभा क्षेत्र-86 जगदलपुर के मतदान केंद्र क्रमांक-221 चिंगपाल-02 का माध्यमिक शाला मांझीगुड़ा (चिंगपाल), मतदान केंद्र क्रमांक-229 लेंड्रा-02 का उच्च प्राथमिक शाला लेंड्रा, मतदान केंद्र क्रमांक-240 एलेंगनार का प्राथमिक शाला झीरम कक्ष क्र.-02 और विधानसभा क्षेत्र- 87 चित्रकोट के मतदान केंद्र क्रमांक-218 करका का पंचायत भवन करका किया गया है।

इसके अलावा मतदान केंद्रों के नाम परिवर्तन के तहत विधानसभा क्षेत्र-85 बस्तर के मतदान केंद्र क्रमांक 67 बागमोहलई कोरागुड़ा का प्राथमिक शाला कोसमयागुड़ा बागमोहलई, मतदान केंद्र क्रमांक 88 बड़े चकवा 2 का प्राथमिक शाला कुरलुगुड़ा, मतदान केंद्र क्रमांक-125 टिकरालाहंगा का उच्च प्राथमिक शाला टिकरालोहंगा, मतदान केंद्र क्रमांक-138 मोंगरापाल-2 शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोंगरापाल, मतदान केंद्र क्रमांक-175 राजनगर 3 का शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला राजनगर,मतदान केंद्र क्रमांक- 209 चितालूर का कनिष्ठ प्राथमिक शाला चितालूर, मतदान केंद्र क्रमांक-140 चोलनार 2 का उच्च प्राथमिक शाला नवीन चोलनार किया गया है।

विधानसभा क्षेत्र-86 जगदलपुर के मतदान केंद्र क्रमांक-11 बालीकोंटा का उच्च प्राथमिक शाला बलिकोन्टा, मतदान केंद्र क्रमांक-16 धरमपुरा 4 का उच्च प्राथमिक शाला धरमपुरा-1 ग्रामीण, मतदान केंद्र क्रमांक-23 गरावंडकला का प्राथमिक शाला बड़ेगारावंड, मतदान केंद्र क्रमांक-71 आड़ावाल-03 का प्राथमिक शाला नयापारा आड़ावाल, मतदान केंद्र क्रमांक-95 फ्रेजरपुर- 07 का कार्यालय इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण मौसम विज्ञान जगदलपुर, मतदान केंद्र क्रमांक-175 परपा-02 का समग्र शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला पटेलपारा पंडरीपानी मावलीगुड़ा, मतदान केंद्र क्रमांक-176 पंडरीपानी-1 का उच्च प्राथमिक शाला पामेला,मतदान केंद्र क्रमांक-179 बिरिंगपाल का उच्च प्राथमिक शाला बिरिंगपाल पटेलपारा, मतदान केंद्र क्रमांक-224 महकापाल का बालक आश्रम शाला महकापाल और मतदान केंद्र क्रमांक-226 सेड़वा का उच्च प्राथमिक शाला सेड़वा किया गया है।

विधानसभा क्षेत्र-87 चित्रकोट के मतदान केंद्रों के नाम परिवर्तन तहत मतदान केंद्र क्रमांक-216 छिंदावाड़ा का माध्यमिक शाला छिंदावाड़ा,मतदान केंद्र क्रमांक-217 छिंदावाड़ा -03 का माध्यमिक शाला रामपाल छिंदावाड़ा, मतदान केंद्र क्रमांक-226 कुकनार-2 का प्राथमिक शाला भण्डाररास अतिरिक्त कक्ष में किया गया। इसके अलावा आंशिक नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बस्तर जिले के मतदान केंद्र-210 भानपुरी-1 को प्राथमिक पाठशाला बड़ेपारा,मतदान केंद्र-211 भानपुरी-2 को प्राथमिक पाठशाला फरसागुड़ा भानपुरी, मतदान केंद्र-212 भानपुरी-3 शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फरसागुड़ा,मतदान केंद्र-237 नंदपुरा (अमलीगुड़ा) को प्राथमिक शाला अमलीगुड़ा, मतदान केंद्र-260 राजपुर-2 को प्राथमिक शाला राजपुर-2 और मतदान केंद्र-264 सोनारपाल -2 माध्यमिक शाला बंजारापारा सोनारपाल किया गया।

सभी सरकारी स्कूलों-कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक दी जाएगी मुफ्त शिक्षा : बघेल

- मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की मौजूदगी में किया पांचवीं घोषणा

कांकेर। भानुप्रतापपुर में राहुल गांधी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पांचवीं घोषणा की जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों/कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। है। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी वादों को पूरा किया है। हम गरीब और भाजपा अडानी को मदद करती है। केंद्र सरकार हर चीज अडानी को दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी जाति जनगणना से क्यों डरते है? यूपीए सरकार के आंकड़ों को मोदी जारी करें।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार किसान के विरोध में लगातार काम कर रही है जब कांग्रेस ने कर्जमाफी की घोषणा की तो भाजपाइयों के पेट में दर्द हो रहा है। रमन सरकार ने चुनाव से पहले खूब राशन कार्ड बनाया पर चुनाव के बाद हजारों राशन कार्ड को निरस्त कर दिया। आदिवासियों के एक लाख एकड़ जमीन छीनने का काम रमन सरकार ने किया, 15 साल में रमन सरकार पेसा कानून तक नहीं बना पाया। मोदी सरकार ने सबके खाते में 15-15 लाख देने का वादा किया था, रोजगार देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था पर एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। ऐसा कोई सगा नहीं है, जिसे रमन सिंह और दिल्ली वालों ने ठगा नहीं। हमने कांग्रेस सरकार बनते ही शपथ लेने के बाद दो घंटे में ही 19 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। 1700 आदिवासी किसानों को जमीन का पट्टा दिया, 4000 प्रति मानक बोरा से तेंदूपत्ता खरीदा जा रहा, सबसे ज्यादा गन्ना और मिलेट्स की कीमत छत्तीसगढ़ में है। चुनाव के बाद बस्तर में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के समक्ष अपनी पांचवीं घोषणा की जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों/कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शानदार मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 3000 रुपये तक धान की खरीदी होगी, लघु वनोपजों की एमएसपी पर अतिरिक्त 10 रुपए दिए जाएँगे तथा तेंदूपत्ता पर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांकेर ज़िले की जनता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया और वादे से ज्यादा दिया। इसलिए उनका है भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार।

बीजेपी बौखला गई है, 12 साल पुराने केस में डिस्टर्ब कर रही

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने चर्चा में आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बौखला गई है, वो राजस्थान में भी बुरी तरह से हारने वाले हैं। वजह से इस तरह के बयान दे रही है। 12 साल पुराने केस में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। राजस्थान में छापे डालने का मतलब है कि वहां पर डिस्टर्ब करना चाहते हैं। यह उनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है।

बीजेपी के शिष्टाचार के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा को खुद ही शिष्टाचार का पालन नहीं करना चाहिए। उपदेश कुशल बहुतेरे कहावत को दोहराते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री की बेटी है, पोती है तो सोनिया गांधी भी तो किसी की पत्नी हैं, किसी की बहू हैं। उसके बारे में भी बीजेपी के नेताओं ने क्या-क्या नहीं कहा, उन्हें भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जैसे ही बनी उन्होंने किसानों को बोनस देना बंद कर दिया। मेरे सवाल उठाने पर 10 क्विंटल धान खरीदने का बीजेपी ने फैसला किया था। किसानों को 2 साल का बोनस नहीं मिला है। इसके लिए मैंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। रमन सिंह ने 2 साल का बोनस नहीं दिया है, मैं देना चाहता हूं पर अभी तक केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी है। सीएम ने कहा कि यदि वो मुझे अनुमति दे दें तो मैं किसानों को दो साल का बोनस दे दूं। भूपेश बघेल ने दावा करते हुए कहा कि किसानों को जो हम सुविधा दे रहे हैं, वह कई प्रदेश में कहीं नहीं मिल रहा है। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 15 लाख सभी के खाते में पहुंच गए, सबके अच्छे दिन भी आ गए।

नई घोषणाएं करने से पहले पुराना हिसाब दें राहुल गांधी, भूपेश की खुद की गारंटी नहीं : अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सवाल करते हुए पूछा कि नई घोषणाएं करने से पहले वो पुराना हिसाब बताएं। उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए कि 5 साल पहले किए गए वादे अब तक नहीं निभाए तो अब नई-नई घोषणाएं करने का उन्हें नैतिक अधिकार कैसे हैं? पहले के चुनाव में की गई अपनी घोषणाओं का छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब दें? उन्होंने पूछा कि छत्तीसगढ़ में 200 फूड प्रोसेसिंग प्लांट कहां हैं? छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी से पूछा कि नक्सल प्रभावित हर पंचायत को 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं मिला? शराबबंदी लागू क्यों नहीं हुई? सभी को चार गैस सिलेंडर मुफ्त में क्यों नहीं मिले? महिलाओं की 1500 की पेंशन कहां है? कर्मचारियों का नियमितीकरण कहां है? छात्रों को 5 साल तक मुफ्त परिवहन क्यों नहीं मिला? बेरोजगारों के 15 हजार करोड़ रुपए कहां गए? न भत्ता दिया न रोजगार दिया। अब तक 700 से ज्यादा घोषणाएं की जा चुकी हैं। साव ने कहा कि भूपेश बघेल और राहुल गांधी मिलकर घोषणाओं का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने में लगे हैं, लेकिन जनता इनके किसी भी वादे पर ऐतबार नहीं कर सकती। क्योंकि 5 साल तक जनता ने कांग्रेस की धोखेबाजी झेली है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव के घोषणा पत्र में करीब 300 वादे किए थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की जनता से कुल मिलाकर 400 के करीब वादे कर चुके हैं। इसके बाद हर रोज घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं।

भाजपा पर बरसे राहुल, उद्योगपतियों की मदद करने का लगाया आरोप

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस राज्य में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। आज कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी कांकेर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहल ने कहा कि आज देश में खदान, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, अडानी जी को दिए जाते हैं। किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वह कानून अडानी जी की मदद करते हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में सेब का पूरा व्यापार अडानी जी के हाथ में है। जम्मू-कश्मीर में भी सेब का पूरा व्यापार अडानी जी के पास है, वे जो भी करते हैं देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करते हैं। अपने संबोधन में राहुल ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने दो घंटे में वो कर दिखाया जो भाजपा ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। 26 लाख किसानों को 23 लाख करोड़ रुपए दिये गए, 5 लाख मजदूरों को 7000 रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हमने छत्तीसगढ़ से 2-3 बड़े वादे किए थे। किसानों की फसलों का सही दाम, किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ होगा। जब हम ये वादे कर रहे थे, तो क्करूमोदी से लेकर क्छ्क के बड़े नेताओं ने कहा था- ये वादे पूरे नहीं होंगे। लेकिन हमने सरकार बनते ही उस काम को 2 घंटे में पूरा कर दिखाया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका- सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, दूसरा तरीका- गरीब लोगों की मदद करो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों और बेरोजगारों की मदद करती है। लेकिन क्छ्क सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की मदद करती है। वहीं, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात भूल जाइए, वे (बीजेपी) तीन कृषि कानून लेकर आए। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया और विरोध के दौरान 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। वे हमेशा किसानों के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई गाथा नहीं, जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं।

संक्षिप्त समाचार

आज कवर्धा आएंगे राहुल गांधी, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित

कबीरधाम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार 29 अक्टूबर को कवर्धा के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे कबीरधाम जिले की कवर्धा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मो. अकबर और पंडरिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीलकंठ (नीलू) चन्द्रवंशी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करेगे। जिले के कांग्रेस नेता चोवा साहू ने बताया कि रविवार को राहुल गांधी हैलीकॉप्टर से राजनांदगांव जाएंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब एक बजे हैलीकॉप्टर से कवर्धा आएंगे। कवर्धा के स्थानीय सरदार पटेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, कवर्धा कांग्रेस प्रत्याशी मो. अकबर, पंडरिया विधानसभा प्रत्याशी नीलकंठ (नीलू) चन्द्रवंशी सहित बड़ी संख्या में प्रदेश व जिला कांग्रेस कमेटी के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

भाजपा ने नियुक्त किए चुनाव संयोजक व समन्वयक

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जिला चुनाव संयोजको व समन्वयकों की नियुक्ति की है। उक्त जानकारी प्रदेश एवं मुख्यालय प्रभारी केदार कश्यप के द्वारा दी गई। जिला चुनाव संयोजकों में रायपुर ग्रामीण- श्री श्याम नारंग, भिलाई- श्री शिरीष अग्रवाल, सक्ती- गोपी सिंह ठाकुर तथा सूरजपुर से श्री भीमसेन अग्रवाल शामिल है। जिला चुनाव समन्वयकों में बलौदाबाजार, सारंगढ़-बिलाईगढ़ - गौरीशंकर अग्रवाल, बालोद - श्रीमती रमशीला साहू, दुर्ग- श्री चंदूलाल साहू, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान- गंडई, मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी- अशोक शर्मा व प्रदीप गांधी, जांजगीर-चांपा- श्रीमती कमला पाटले, सक्ती- श्री निर्मल सिन्हा व कोण्डागांव में संतोष बाफना शामिल है। जिला चुनाव संयोजकों में रायपुर ग्रामीण- श्री श्याम नारंग, भिलाई- श्री शिरीष अग्रवाल, सक्ती- गोपी सिंह ठाकुर तथा सूरजपुर से श्री भीमसेन अग्रवाल शामिल है। जिला चुनाव समन्वयकों में बलौदाबाजार, सारंगढ़-बिलाईगढ़ - गौरीशंकर अग्रवाल, बालोद- श्रीमती रमशीला साहू, दुर्ग- श्री चंदूलाल साहू, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान- गंडई, मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी- अशोक शर्मा व प्रदीप गांधी, जांजगीर-चांपा- श्रीमती कमला पाटले, सक्ती - श्री निर्मल सिन्हा व कोण्डागांव में संतोष बाफना शामिल है।

छत्तीसगढ़ व्यापमं की भर्ती परीक्षा आज

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 29 अक्टूबर रविवार को आयोजित विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाएं राज्य के 31 जिला मुख्यालयों में दो पालियों में आयोजित होंगी। परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीएएस 23 भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन 15 अक्टूबर को किया जाना था, उसे स्थगित करने के पश्चात अब यह परीक्षा 29 अक्टूबर 2023 रविवार को छत्तीसगढ़ राज्य के 31 जिला मुख्यालयों में दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली पूर्वान्ह 10 बजे से 12.15 बजे तक सहायक प्रबंधक (फिल्ड ऑफिसर)/कार्यालय सहायक/सामान्य सहायक/समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) की भर्ती परीक्षा ली जाएगी, जबकि दोपहर 2 बजे से अपरान्ह 4.15 बजे तक कनिष्ठ प्रबंधक (2)/कनिष्ठ प्रबंधन संवर्ग (ट्रेजरी विशेषज्ञ/मुख्य लेखापाल/उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक की भर्ती परीक्षा ली जाएगी।

भाजपा ने जारी किया कांग्रेस के परदेसीया लापता सांसदों का पोस्टर

- भूपेश है तो भरोसा है का दौर आने से पहले खत्म हुआ, हम नहीं चरण दास महंत का बयान इसका संकेत - श्रीवास्तव

रायपुर। भूपेश है तो भरोसा का दौर खत्म हो गया, ये हम नही कांग्रेस नेताओं के बयान बता रहे है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरण दास महंत ने कह दिया कि कांग्रेस का फिलहाल कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लडा जा रहा है अगर सत्ता आई तो दिल्ली में मुख्यमंत्री तय होगा यानी अब कांग्रेस ने बिलकुल साफ कर दिया की उन्हे भूपेश बघेल पर भरोसा नही है। उससे पहले भी मुख्यमंत्री के कई बार विरोध के बाद भी टी एस सिहदेव को दिल्ली से आदेश कर उपमुख्यमंत्री बनाया था। उक्त बातें आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा प्रवक्ता श्री संजय श्रीवास्तव ने कही।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ कोटे से राज्यसभा भेजे गए सांसदों के बारे में कहा की वो कहा लापता है।राहुल गांधी उन्हे छत्तीसगढ़ टूर पर ही ले आते कम से कम जनता अपने राज्यसभा सांसदों के चेहरे तो देख लेती ।संजय श्रीवास्तव ने कहा भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगो का हक मारा है छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगो को राज्यसभा भेजना पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान है और जनता अपना हक मारने वालो को सबक सिखाने जा रही है।राहुल गांधी बताए उनके ये छत्तीसगढ़ के सांसद कहा लापता है। इसी दौरान प्रदेशनप्रवक्ता संजय श्रीवास्तव और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने लापता राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी करते हुए पूछा ये सांसद कहा लापता है।

उत्तर और पश्चिम विधानसभाओं के हर पोलिंग बूथ पर तैनात होंगी महिलाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार महिला ब्रिगेड पोलिंग बूथों पर मोर्चा संभालती दिखेंगी।बात यदि विधानसभा चुनाव की करें तो इस बार यहां होने वाला मतदान ऐतिहासिक होगा।रायपुर जिले में दो विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा महिलाओं के जिम्मे होगा। यहां टॉप से लेकर यूनिट तक निर्वाचन का कार्य महिलाओं को सौंपा गया है। यह विधानसभा में उत्तर और पश्चिम है।जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष बूथ संगवारी केंद्र बनाए हैं। रायपुर जिले के उत्तर और पश्चिम विधानसभा में सभी बूथों को संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया है। उत्तर विधानसभा में 18 सेक्टर हैं। इसमें 01 सेक्टर में महिला अधिकारी होंगी। वहीं 265 मतदान केन्द्र 1 हजार 60 महिला अधिकारियों के जिम्मे होंगे।265 बूथ में पीठासीन अधिकारी, मतदान क्रमांक 01,02,03 में सभी जगहों पर महिला अधिकारी-कर्मचारी को तैनात किया जाएगा। यहां 265 पीठासीन अधिकारी और 7 सौ 95 मतदान अधिकारी रहेंगे।

उत्तर विधानसभा की मुख्य ऑब्जर्वर 01 महिला आई।ए।एस अधिकारी विमला आर। है। साथ ही उनकी लाईजिनिंग ऑफिसर भी महिला ही है। साथ ही अधिक से अधिक महिला पुलिस बल भी तैनात किए जा रहे हैं। यहां पर मतदान पर्ची चेक करने से लेकर उंगली में स्याही लगाने और रजिस्टर में हस्ताक्षर के साथ वोटिंग करवाने तक महिलाएं ही नजर आएंगी।

पश्चिम विधानसभा को भी पूरे तरीके से महिला अधिकारियों के जिम्मे सौंपने की तैयारी की गई हैं। पश्चिम विधानसभा में 15 सेक्टर और 201 मतदान केन्द्र हैं। यहां भी एक सेक्टर महिला अधिकारी होंगी। साथ ही बूथों में 804 महिला अधिकारी होंगी। जिनमें 201 पीठासीन अधिकारी और 603 मतदान अधिकारी होंगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने बताया कि जिले के इस बार 02 विधानसभा उत्तर और पश्चिम में निर्वाचन कार्य में पूर्ण रूप से महिलाओं की तैनाती की जा रही है।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भूरे ने कहा महिला अधिकारी-कर्मचारी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करती हैं यह सराहनीय है। यह प्रयास किया जा रहा है कि उनकी ड्यूटी मतदान केन्द्र सहित जहां भी लगाई जाएगी वहां पर उनके लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि उन्हे कोई तकलीफ ना हो।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आपराधिक छवि वाले नेताजी

रायपुर। छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक 223 उम्मीदवारों में से 26 यानी 12 फीसदी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन में अपराध की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। बाकी बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे

पहले चरण के उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी के 20 उम्मीदवारों में से 5 यानी 25 फीसदी उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के 20 में से दो यानी दस फीसदी उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के चार यानी 20 फीसदी उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के 15 उम्मीदवारों में से तीन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 निर्वाचन क्षेत्रों में से पांच सीटों कांकेर, चित्रकोट, खैरागढ़, पंडरिया और कवर्धा सीटों पर तीन या अधिक आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों का आमना सामना होगा।

बीजेपी उम्मीदवारों विजय शर्मा (कवर्धा सीट), विक्रांत सिंह (खैरागढ़), विनायक गोयल (चित्रकोट-एसटी), आशाराम नेताम (कांकेर-एसटी) और सोयम मुक्का (सुकमा-एसटी) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं।वहीं कांग्रेस से शंकर ध्रुवा (कांकेर-एसटी) और नीलकंठ चंद्रवंशी (पंडरिया), आप से नरेंद्र भवानी (जगदलपुर), कोमल हुपेंडी (भानुप्रतापपुर), बोमधा मंडावी (चित्रकोट) और खगदराज सिंह (कवर्धा) ने अपने नामांकन में आपराधिक जानकारी दी है। इसके अलावा जेसीसीजे के रवि चंद्रवंशी (पंडरिया), लकी मंगल नेताम (खैरागढ़) और सोनसाय कश्यप (बस्तर) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

पहले चरण में कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, मोहला-मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग होगी।इन सभी सीटों पर 223 उम्मीदवार मैदान में हैं।

अवैध शराबखोरी पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, 1.9 करोड़ की नशीले पदार्थ जब्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद आबकारी विभाग अवैध शराब की रोकथाम के लिए सघन जांच अभियान चला रही है। इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से कुल 1.97 करोड़ रुपए कीमत की शराब, वाहन, गांजा और महुआ लाहन जब्त की है। वहीं अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में 31 चेकपोस्ट के माध्यम से आने जाने वाले गाड़ियों की जांच की जा रही है। अवैध शराब और दुकानों से संबंधित शिकायत करने के लिए टोल-फ्री नंबर 14405 भी लागू की गई है।

आबकारी विभाग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 9 से 26 अक्टूबर तक सघन कार्रवाई अभियान चलाकर 2 हजार 38 जगहों पर छापे मारी हैं। इस दौरान 929 प्रकरण दर्ज कर 825 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। विभाग ने इस दौरान 11 हजार 833 लीटर शराब जब्त की है, जिसका बाजार मूल्य 35 लाख 36 हजार 104 रुपए है। विभाग ने इस अवधि में 59 लाख 90 हजार 600 रुपए कीमत का महुआ लाहन और गांजा भी जब्त किया है। इस दौरान 45 गाड़ी भी जब्त की गई है। जब्त गाड़ियों की कीमत मिलाकर आबकारी विभाग ने कुल 1 करोड़ 96 लाख 83 हजार 704 रुपए जब्त किया है। इसके साथ ही राज्य के सीमावर्ती जिलों में स्थापित आबकारी विभाग के 31 चेकपोस्टों में कई राज्यों से अवैध शराब का परिवहन रोकने के लिए गाड़ियों की जांच की जा रही है। आबकारी अमले की ओर से कई जगहों पर रोड चेकिंग के साथ ही रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस के साथ मिलकर रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, बस अड्डों और बसों पर भी जांच कर रही है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रवर्तन एजेंसियों ने समीक्षा बैठक ली थी। इस दौरान विशेष सचिव सह आबकारी आयुक्त महादेव कावरे ने आबकारी विभाग के सभी उड़नदस्ता समेत विभाग के कर्मचारी को अवैध शराब बिक्री निगरानी का निर्देश दिए थे। इसके साथ ही प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सघन जांच अभियान चलाने और संचालित जांच चौकियों में जांच बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कांग्रेस के दबाब में भाजपा के प्रचार में बाधक बन रहा प्रशासन : मांडविया

- कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं राज्य के अफसर
- ढेरों शिकायतों के साथ भाजपा पहुंची चुनाव आयोग

रायपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव सह प्रभारी मनसुख भाई मांडविया के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग में जाकर शिकायत की। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हर क्षेत्र से शिकायत मिल रही है। कांग्रेस प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। जगह जगह अधिकारी चुनाव को प्रभावित करने भय का माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सामग्री, पार्टी का झंडा लेकर जाने वाली गाडियों को रोक रहे हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति किसी को भी वोट दे सकता है और यह हर नागरिक का अधिकार है कि वह किसी भी पार्टी का चुनाव प्रचार भी कर सकता है। अपने घर में झंडा लगा सकता है।

राजनीतिक पार्टी अनुमति लेकर किसी के भी घर में झंडा लगा सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर में झंडा लगाते हैं तो उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं को डराने के लिए उनकी हत्याएं हो रही हैं। हत्या करने वाले सार्वजनिक तौर पर चौलेंज भी करते हैं। उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। दंतेवाड़ा नारायणपुर बीजापुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। लोगों को डरने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव हो इसलिए हमने आज चुनाव आयोग में अपनी बात रखी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा चुनाव सह प्रभारी श्री मांडविया ने कहा कि आज तक जितनी भी शिकायत हमने चुनाव आयोग में दर्ज कराई हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि उन शिकायतों पर तत्काल उचित कार्यवाही हो। छत्तीसगढ़ के अधिकारी निष्पक्ष रूप से कार्य करें। सरकार के दबाव में न आएं। लोकतंत्र की चिंता करें और लोकशाही प्रक्रिया का पालन करें। अगर हमारी शिकायतों का समाधान नहीं होता है तो हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग में जाएंगे और इनकी शिकायत करेंगे। यह तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता निष्पक्ष रूप से किसी के भय में न आकर अपने वोट का उपयोग करके अपनी पसंद की सरकार चुने। हमने निर्वाचन आयोग में अपनी बात आग्रह पूर्वक रखी है और हमने कहा है कि चुनाव आयोग पर हमारा विश्वास है कि चुनाव आयोग हमारी शिकायतों का निराकरण करेगा। इस दौरान सांसद सुनील सोनी, निर्वाचन समिति के संयोजक विजय शंकर मिश्रा, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, प्रदेश मीडिया सहप्रभारी अनुराग अग्रवाल भी मौजूद थे।

अनिश्चित है शिवराज सिंह चौहान का भविष्य

आदिति फडणीस

वह जीत की उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की पांचवीं सूची में उन्हें बुधनी से उम्मीदवार बनाया। जब शुरुआती चार सूचियों में उनका नाम नहीं नजर आया तो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता से पूछा, 'बताइए चुनाव लड़ूं या नहीं? यहां से लड़ूं या नहीं?' एक अन्य स्थान पर जनसभा में उन्होंने जनता से पूछा, 'बताइए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं?' इन सवालों पर जनता के जवाब ने नहीं बल्कि खुद इन सवालों ने कई की भृकुटियां टेढ़ी कर दी हैं। सीहोर में आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, 'मेरी बहिनों, ऐसा भैया नहीं मिलेगा। जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें याद आऊंगा।' उनकी पीड़ा अन्य घटनाओं से भी सामने आई। यहां दो ऐसे अवसरों का उल्लेख करना उचित होगा। चुनावों की घोषणा के पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के लिए भोपाल आए तो उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। उन्होंने लाड़ली बहना योजना (एक तय स्तर से कम आय वाली महिलाओं को प्रति माह 1,250 रुपये देने की घोषणा जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपये तक किया जाएगा) जैसी शिवराज सरकार की प्रमुख योजनाओं का भी जिक्र नहीं किया। ये ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें मुख्यमंत्री अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि मानते हैं। एक विरोधाभासी बात यह है कि कुछ दिन पहले ग्वालियर में सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा में अपेक्षाकृत नए आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को याद दिलाया कि सिंधिया गुजरात के दामाद हैं और उनके दिल में खास जगह रखते हैं। उन्होंने सिंधिया परिवार, खासकर माधवराव सिंधिया की भी तारीफ की जिन्होंने शताब्दी ट्रेन शुरू की थी जिसे वर्तमान में चल रही वंदे भारत ट्रेनों की पूर्वज माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर दोनों विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों खड़े यह सब खामोशी से सुनते रहे। तोमर के प्रभाव वाला इलाका ग्वालियर से लगा हुआ है और अभी कुछ वर्ष पहले तक उनके समर्थक महाराज को निशाने पर लेते रहे हैं। लेकिन अब वह उनके मूल्यवान सहयोगी हैं और प्रधानमंत्री की बात भला कौन काट सकता है? कई और ऐसे वाकये हैं जो बताते हैं कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की अनदेखी की है। देश में सोयाबीन के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 60 फीसदी है। यह खरीफ की एक महत्त्वपूर्ण फसल है। इस वर्ष असमान वर्षा ने उत्पादन पर बुरा असर डाला है और इसकी क्षतिपूर्ति देने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने गत वर्ष अक्टूबर में हर प्रमुख खाद्य तेल के आयात पर शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया। सोयाबीन सहित आयातित कच्चे खाद्य तेल पर प्रभावी कर दर केवल 5.5 फीसदी है। यानी तेल मिल और सॉल्वेंट निकालने वालों के पास कई सस्ते विकल्प हैं और उन पर किसानों से सोयाबीन खरीदने का कोई दबाव नहीं है। इस बात ने किसानों को हताश किया है। ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान आगे देखने के बजाय मुड़कर पीछे देख रहे हैं यह उनके और उनके समर्थकों के मन में घर कर चुकी नाउम्मीदी के अनुरूप ही है। यह बात पोस्टरों और चुनावी होर्डिंग में देखी जा सकती है। उनमें नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर है जबकि भाजपा के अन्य नेताओं की छोटी सामूहिक तस्वीर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान नेताओं की भीड़ में एक और चेहरा भर हैं। इस सामूहिक तस्वीर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, सिंधिया, तोमर तथा कई अन्य नेता हैं। अतीत में ऐसा नहीं होता था। दिल्ली से संचालित इस रणनीति के पीछे क्या वजह हो सकती है? शिवराज सिंह चौहान चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह पहली बार तब मुख्यमंत्री बने थे जब वह 46 वर्ष के थे।

चुनावी माहौल में ईडी की इंट्री

निरंजन परिहार

राजस्थान में सर्दियों के दिन शुरू हो ही रहे हैं और चुनाव की वजह से राजनीति गरमा रही है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री ने राजस्थान के राजनीतिक माहौल को और गरमाने का सामान बख्श दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के विधायक ओमप्रकाश हुडला पर ईडी अपना शिकंजा कस रही है।

गहलोत और उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही कांग्रेस नेताओं के बचाव में कहते रहें कि केंद्र सरकार और बीजेपी उनकी जनलाभकारी योजनाओं से घबरा रही है और चुनाव हार रही है, इसलिए उनके नेताओं को परेशान करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति के जानकार बताते हैं कि अगला नंबर कांग्रेस सरकार के मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी का भी लग सकता है। दोनों पर सैकड़ों करोड़ रुपयों की सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। वैसे, तो ईडी की कारवाई कभी भी हो सकती है, लेकिन चुनावी माहौल में ये छापे पड़ने से राजनीतिक माहौल में गर्मी आ गई है और पूरी कांग्रेस एकजुट दिख रही है। मुख्यमंत्री गहलोत के कट्टर विरोधी सचिन पायलट भी इस मामले में उनके साथ खड़े दिख रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में विधानसभा उम्मीदवारों की तीसरी सूची पर मशक्कत करते हुए अगली रणनीति पर तैयारी कर रहे थे कि 26 अक्टूबर की सुबह ईडी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और जयपुर में उनके सरकारी निवास सहित सीकर जिले में स्थित उनके गांव वाले घर पर भी छापेमारी शुरू कर दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर ईडी की यह कारवाई राजस्थान में पिछले साल हुए पेपर लीक मामले को लेकर है, जिसमें डोटासरा का नाम भी शामिल था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत को भी ईडी ने सम्मन भेजकर केवल एक दिन के नोटिस पर 27 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलावा भेज दिया। वैभव गहलोत पर ईडी की यह कारवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में सन 2011 में एक होटल के शेयर खरीदने का मामला है, जिसमें कथित तौर पर अनियमितताओं के आरोप है। निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे ओमप्रकाश हुडला ने हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ली है और इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी भी हैं। हुडला के होटल हुडला पार्क, महुआ निवास, रामकुटी ग्राम सहित अन्य ठिकानों पर ईडी ने 26 अक्टूबर को छापे मारे। ईडी की टीमें दौसा, जयपुर सहित कई जगहों पर हुडला के ठिकानों पर पहुंची थी। आरोप है कि हुडला के छोटे भाई हरिओम मीणा और एक डमी कैंडिडेट को जयपुर के शिवदासपुरा में एक एग्जाम सेंटर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई और इन्कम टैक्स विभाग को अपने राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह उनका आखरी दांव है, जो सफल नहीं होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी और अमित शाहजी भले ही मुझे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वे हमें डरा नहीं पाएंगे। वे परेशान हैं क्योंकि वे राजस्थान में सरकार गिरा नहीं पाए, जबकि उन्होंने पांच राज्यों में सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली। गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पर छापों से हम डरने वाले नहीं हैं, ईडी की इस कारवाई के बावजूद हमारी सरकार बनेगी। इसके लिए उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया और कहा कि वहां पर डीके शिवकुमार पर भी इसी तरह के कई हमले हुए और कर्नाटक में से बीजेपी गायब हो गई।

वहीं वैभव गहलोत का कहना है कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और हम जानते थे कि ये सब चुनाव से पहले होगा, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वैभव ने कहा कि यह ईडी ने जिस मामले में उन्हें बुलाया है, वह तो 12 साल पुराना मामला है, जिस पर पहले भी जांच हो चुकी है और वे अपना जवाब दे चुके हैं। ईडी के इन छापों पर सचिन पायलट भी मुखर हैं। हालांकि राजस्थान की राजनीति में पायलट गहलोत के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी गहलोत के बेटे वैभव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा पर ईडी की कारवाई के विरोध में उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस के हमारे नेताओं को नहीं डरा सकती। पायलट ने कहा है कि ईडी के ये छापे बीजेपी में घबराहट की निशानी है। कांग्रेस चाहे कितना भी हंगामा करे, लेकिन ईडी का किसी पर भी कारवाई करने का अपना तरीका है। उसकी कार्रवाई का दायरा बहुत व्यापक है। ईडी को सरलता से समझना हो, तो यह केंद्र सरकार के अधीन एक ऐसी जांच एजेंसी है, जो अवैध धन को वैध करने के बारे में बहुचर्चित शब्द मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित अपराधों की जांच करती है। धनशोधन निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जैसे कानूनों के तहत मिले अधिकारों पर अपने विशेषाधिकार के अनुरूप काम करती है। ईडी अपनी कार्रवाई के लिए न तो समय देखती है और न ही अवसर। पिछले कुछ सालों में इसकी सक्रियता कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है, खासकर राजनीति से जुड़े लोगों पर ईडी की कारवाई पर उंगलियां उठती रही हैं। लेकिन अवैध धन के लेन देन तथा उसे वैध करने की कोशिशों के ज्यादातर मामले भी राजनीतिकों के द्वारा ही होते रहे हैं। इसीलिए राजनेताओं पर आजकल ईडी के छापे ज्यादा पड़ रहे हैं, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पहले राजनेताओं पर कार्रवाई ही नहीं होती थी, तो मामले बाहर भी नहीं आते थे। मगर राजनीति में आर्थिक पारदर्शिता व नेताओं को राजनीतिक आचरण में शुद्धता के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी भी है, इसलिए ईडी जैसी संस्था को सभी पार्टियों के भ्रष्ट राजनेताओं पर कार्रवाई तेज करनी चाहिए। कुल मिलाकर ईडी अब राजस्थान में सक्रिय है, जिससे कांग्रेस और कांग्रेसियों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़े नेता बचाव के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और कांग्रेस केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बनाने के आरोप लगा रही है। मगर खबर है कि ईडी का यह ऑपरेशन आनेवाले दिनों में और विस्तार लेगा, क्योंकि एक बार जब ईडी आ जाती है, तो हर मामले की वह बहुत गहराई से जांच करती है और आगे से आगे लोग उसकी जकड़न में आते जाते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसीलिए कहा है कि ईडी का यह टिड्डी दल की तरह हमला है। गहलोत ने कहा है कि सवाल मेरे बेटे या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं है, बल्कि ईडी ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। लेकिन सही मायने में देखें, तो ईडी की कारवाई एक सामान्य प्रक्रिया है, जिस पर वह अपने तरीके से अपने समय पर काम करती रही है, फिर चाहे होली हो या दीवाली, विवाह के अवसर हो या चुनाव। अत: चुनाव के दिनों में छापे एक संयोग भी तो हो सकता है। फिर भी राजस्थान में ईडी के ताजा छापों व नोटिस को राजनीतिक नजरिये से देखा जाना भी वाजिब है, क्योंकि सरकार पर ईडी को अपने हक में इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं, फिर वक्त राजनीति का है और सवाल चुनाव में जीत का भी है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-27)

गतांक से आगे...

शास्त्रानुकूल आचरण से, स्वयं के एकत्रित अनुभवजन्य ज्ञान प्रकाश से तथा विवेक बुद्धि से मनरूपी पिता परमसिद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। अति हृष्ट-पुष्ट, सुदृढ़, निर्मल, स्ववशीभूत, भली प्रकार चैतन्य तथा आत्मिक सद्गुणों से प्रखर तेजस्विता युक्त सुन्दर मनरूपी मणि हृदय में विराजमान है।

हे ब्रह्मन्! बहुविध वासना तृष्णा के कीचड़ से सने इस मनरूपी मणि को विवेक रूपी जल से निर्मल करके साधन-सिद्धि के लिए चमकदार (परिष्कृत) बनायें। सद्विवेक का अवलम्बन लेकर, बुद्धि से यथार्थ सत्य का अनुसन्धान करके इन्द्रियरूपी वैरियों को तुम छिन्न-भिन्न कर पाओगे, इसी से संसार रूपी भवसागर से तुम पार उतरने में सक्षम हो सकोगे।

संसार में मात्र आस्था (आशा) ही अनेक कष्टों की उत्पत्ति का कारण है और अनास्था (आशा-अपेक्षारहित जीवन) ही सुख का घर समझना चाहिए। वासनाओं के सूत्र से बंधा हुआ यह संसार पुन: पुन: उत्पन्न होता है। वह प्रख्यात वासना अति कष्टदायिनी बनकर समस्त सुखों का पूरी तरह से उच्छेदन करने के लिए आती है। जंजीर से सिंह के बाँधने के समान वासना के मोहपाश में धीर, कुलीन, अति बहुश्रुत तथा महान् व्यक्ति भी बँध जाते हैं। शास्त्रानुकूल आचरण करता हुआ, परम पुरुषार्थ का अवलम्बन लेकर और श्रेष्ठ उद्यम करते हुए कौन सिद्धि को प्राप्त नहीं करता?

मैं समस्त विश्वरूप हूँ, मैं अच्युत परमात्मस्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त शेष कुछ भी नहीं इस तरह के बोधात्मक अहंभाव को उत्तम माना गया है। मैं सभी प्रपञ्च से भिन्न हूँ, मैं बाल के अग्रभाग से कहीं अधिक सूक्ष्म हूँ इस प्रकार का दूसरा अहं भाव मोक्ष को देने वाला है, बन्धन में फँसाने वाला नहीं। जीवन्मुक्त आत्मायें ही ऐसे अहंभाव से युक्त होती हैं।

मैं हाथ-पैर वाला मात्र स्थूल शरीरधारी हूँ इस प्रकार की मान्यता जो तीसरे लौकिक अहंकार में होती है, उसे अत्यन्त निकृष्ट कहा गया है। अहंकार से युक्त दुरात्मा प्राणी ही कष्टमय संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण है। इससे प्रताड़ित प्राणी निरन्तर पतन की ओर बढ़ता है। इस तृतीय दु:खमय अहंभाव का परित्याग करके लम्बे समय से शुभ अहंभाव में संलग्न प्राणी शान्तचित्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं।

प्रारम्भिक दो अलौकिक अहंकारों को स्वीकार करके तीसरे दु:खप्रद लौकिक अहंकार को त्याग दे । साधन शक्ति की वृद्धि पर इन सब प्रकार के अहंकारों को त्यागकर निरहंकारिता ग्रहण करे, उसी से उत्तमपद की प्राप्ति सम्भव है। भोगेच्छा ही बन्धन कही गयी है और उसका परित्याग ही मोक्ष कहलाता है। मन की प्रगति का कारण उसका नष्ट होना है। मन का नाश सौभाग्यवान् पुरुषों की पहचान है। ज्ञानी पुरुषों के मन का नाश हो जाता है। अज्ञानी के लिए मन बन्धन का कारण है।

क्रमश: ...

भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे डॉ. होमी जहांगीर भाभा

अभिनय आकाश

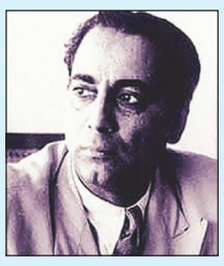

होमी जहांगीर भाभा यानी विज्ञान की दुनिया का ऐसा चमकदार सितारा जिसका नाम सुनते ही हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है बचपन से ही विज्ञान की दुनिया में गहरा लगाव रखने वाले भाभा न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह एक इंजीनियर, संगीतकार और बेहतरीन कलाकार भी थे। भाभा देश और दुनिया के लिए जाना-माना नाम है। दरअसल भाभा ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की और भारत को परमाणु ऊर्जा संपन्न और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रसर बनाकर दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया।

होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्तूबर, 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता जहांगीर भाभा एक जाने-माने वकील थे। होमी भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से हुई। इसके बाद आगे की शिक्षा जॉन केनन स्कूल में हुई। भाभा शुरू से ही भौतिक विज्ञान और गणित में खास रुचि रखते थे। डॉ भाभा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद साल 1939 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद वह बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़ गए, और साल 1940 में रीडर के पद पर नियुक्त हुए।

भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के मिशन में प्रथम कदम के तौर पर उन्होंने मार्च, 1944 में सर दोराब जे. टाटा ट्रस्ट को मूलभूत भौतिकी पर शोध के लिए संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा। साल 1948 में डॉ भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। साल 1955 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित 'शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग' के पहले सम्मलेन में डॉ. होमी भाभा को सभापति बनाया गया।

होमी जहांगीर भाभा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के पक्षधर थे। 60 के दशक में विकसित देशों का तर्क था कि परमाणु ऊर्जा संपन्न होने से पहले विकासशील देशों को दूसरे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर भाभा ने इसका खंडन किया। भाभा विकास कार्यों में परमाणु ऊर्जा के प्रयोग की वकालत करते थे। वर्ष 1957 में भारत ने मुंबई के करीब ट्रांबे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। वर्ष 1967 में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। यह होमी भाभा को देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि थी। इस संस्थान ने एक विशिष्ट नाभिकीय अनुसंधान संस्थान के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। आज यहाँ नाभिकीय भौतिकी, वर्णक्रमदर्शिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान, रिएक्टर इंजीनियरी, यंत्रीकरण, विकिरण संरक्षा एवं नाभिकीय चिकित्सा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान हो रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि हम परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करेंगें। लेकिन, उनकी मृत्यु के बाद परिदृश्य में आये बदलाव ने भारत की परमाणु नीति को प्रभावित किया। भारत की सुरक्षा को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने भारत को परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता से मुक्त कर दिया। वर्ष 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया, तो भारत का चिंतित होना स्वाभाविक था। वर्ष 1965 में, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो यह चिंता बढ़ गई। ऐसे में, सामरिक संतुलन के लिहाज से भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की जरूरत अनुभव की जाने लगी। 18 मई, 1974 को भारत ने पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 24 जनवरी, 1966 को एक विमान दुर्घटना में भारत के इस प्रमुख वैज्ञानिक और स्वपनद्रष्टा की मृत्यु हो गई।

आतंक का आका कतर बना रहा है भारत पर दबाव

संजय तिवारी

इसी साल अप्रैल महीने की बात है। उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि कतर में गिरफ्तार किये गये 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। जयराम रमेश ने कहा था कि ऐसा इसलिए क्योंकि अडानी इलेक्ट्रिसिटी, मुंबई में कतर का सावरेन वेल्थ फंड लगा हुआ है। इस पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हम कतर पर दबाव नहीं बना सकते। हमें नहीं लगता कि दो देशों के अच्छे संबंध का असर उनके यहां की कानूनी कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन हम परिस्थितियों पर नजर बनाये हुए हैं।

आज लगभग 6 महीने बाद जब उन सभी 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी गयी है तब उसी विदेश मंत्रालय के वही प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम फांसी दिये जाने के फैसले से स्तब्ध हैं। इसका अर्थ यह है कि एक ही मामले में आज से 6 महीने पहले भारत का विदेश मंत्रालय जो आकलन करके चल रहा था, निर्णय उसके विपरीत आ गया तो वह स्तब्ध रह गया। संभवत: विदेश मंत्रालय को उम्मीद थी कि अल दहरा कंपनी में काम करनेवाले भारत के आठ पूर्व नेवी कर्मचारियों/अधिकारियों को जासूसी के आरोप से मुक्त करके रिहा करवा लिया जाएगा। लेकिन कतर के कोर्ट ने उन्हें जासूसी का दोषी पाया और फांसी की सजा सुना दी।

असल में भारत के जिन 8 नागरिकों को फांसी की सजा सुनायी गयी है वो सभी वहां अल दहरा टेक्नॉलाजी नामक एक निजी कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी भारत के एक पूर्व नौसैनिक कमांडर

पूर्णेन्दू तिवारी ने बनायी थी। ये सभी लोग वहां कतर के लिए किसी स्माल स्टील्थ वारशिप के प्रोजेक्ट में तकनीकी मदद कर रहे थे। पिछले साल अगस्त 2022 में इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर आरोप लगा कि ये लोग इजरायल के लिए जासूसी करते हैं। इस गिरफ्तारी के बाद अल दहरा कंपनी बंद हो गयी। जो आठ लोग गिरफ्तार किये गये उनमें 7 नेवी के रिटायर्ड कमांडर या कैप्टन हैं जबकि एक पूर्व नौसैनिक है।

भारत के लिए यह कोई सामान्य घटना नहीं थी कि कतर में एक साथ आठ भारतीय पूर्व सैनिक गिरफ्तार कर लिये जाएं। काउन्सलर एक्सेस के जरिए भारत सरकार की ओर से कानूनी मदद भी दी गयी लेकिन आखिरकार कतर के कोर्ट में जासूसी का दोष सिद्ध हो गया। अब क्योंकि कतर में देशद्रोह और जासूसी के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है इसलिए आरोप सिद्ध होने के बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गयी।

आगे राजनयिक जगत में उन्हें बचाने के लिए जो कानूनी उपाय करने होंगे वह भारत सरकार की ओर से अवश्य किए जायेंगे लेकिन फिलहाल तो वो सभी कतर की जेलों में ही बंद रहेंगे। इस प्रकरण से इतना तो साफ हो गया है कि कतर को लेकर भारत सरकार का जो भी आकलन रहा हो वह निराधार साबित हुआ है। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब आतंक का आका कहे जानेवाले कतर ने इस तरह से भारत के सामने मुश्किल पैदा की है।

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर नबी निंदा का आरोप लगाकर भारत के मुसलमानों ने खूब उपद्रव किया था। आनन फानन में बीजेपी ने भी उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन उस मौके पर जब अरब का कोई देश भारत के आंतरिक मामले में बोलने से बच रहा था तब कतर ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कतर ने भारत के राजदूत को बुलाकर पूरे मामले को आपत्तिजनक बताया था। तब कतर ने ही यह बात कही थी कि राजदूत ने उन्हें स्पष्ट किया था कि ये भारत सरकार की नीति नहीं बल्कि कुछ फ्रिंज एलिमेन्ट का काम है।

संभवत: कतर का ही दबाव था कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में नुपुर शर्मा और नवीन जिन्दल को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। इस बात के लिए आज तक भाजपा की आलोचना होती है कि जब इन लोगों ने कुछ ऐसा कहा ही नहीं जो इस्लामिक हदीसों में पहले से मौजूद नहीं है तो फिर इन्हें पार्टी से क्यों निकाल दिया गया? लेकिन कतर का मोदी सरकार पर प्रभाव ऐसा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना से अधिक कतर की धमकी का ध्यान रखा गया, यह जानते हुए भी कि कतर घोषित तौर पर आतंक का आका है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक उसे आतंकवाद को फंड करनेवाला कह चुके हैं।

आज से 6 साल पहले उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कहा था कि दुर्भाग्य से कतर बहुत ऊंचे स्तर पर आतंकवाद को पैसे देता है। इसीलिए अरब के कई देश मेरे पास आये और कतर के इस व्यवहार के बारे में शिकायत की। इस बारे में हमारा कहना है कि कतर को आतंकी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए पूंजी नहीं देनी चाहिए। हम सभी देशों से कहना चाहते हैं कि दूसरे के खिलाफ नफरत फैलानेवाले और दूसरों की हत्या करनेवाली शिक्षा और फंड दोनों को बंद करना होगा। हालांकि एक सच यह भी है कि खाड़ी देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस आज भी कतर में ही है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के बारे में यह बात केवल अरब देशों की शिकायत पर बोली हो, ऐसा भी नहीं है। अफगानिस्तान में अगर अमेरिका असफल हुआ तो उसके पीछे कहीं न कहीं कतर की भूमिका और पैसा भी था जो तालिबान के साथ खड़ा था। कतर की राजधानी दोहा तालिबानियों के दूसरे घर जैसा था जहां बैठकर वो अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करने और वहां की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने की योजनाएं बनाते थे। वहीं पर वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपनी गुप्त वार्ताएं करते थे। आखिरकार एक सीमित युद्ध के बाद अगस्त 2021 में तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अमेरिका को वहां से जाने के लिए सेफ एक्जिट दे दिया। कतर पर आरोप है कि तालिबान ही नहीं वह अल कायदा, अल नुसरा, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों को भी हर प्रकार की मदद करता रहा है। एक बार 2014 में सीएनएन ने जब इस बारे में वहां के अमीर शेख तमीम अल थानी से सवाल किया तो उनका जवाब था कि इन संगठनों को वो आतंकी संगठन ही नहीं मानते। वर्तमान समय में जिस हमास ने इजरायल पर हमला किया उस हमास के शीर्ष कमांडर भी कतर में ही बैठे बताये जाते हैं। हमास का लीडर इस्माइल हानिया इस समय कतर में ही रह रहा है।

हिन्द स्वराज्य

मशीनें (भाग-2)

गतांक से आगे...

प्रश्न- तब क्या मिलों को बन्द कर दिया जाय ?

उत्तर- यह बात मुश्किल है। जो चीज स्थायी या मजबूत हो गयी है, उसे निकालना मुश्किल है। इसीलिए काम शुरू न करना पहली बुद्धिमानी है। मिल मालिकों की ओर हम नफरत की निगाह से नहीं देख सकते। हमें उन पर दया करनी चाहिए। वे यकायक मिलें छोड़ दें यह तो मुमकिन नहीं है; लेकिन हम उनसे ऐसी बिनती कर सकते हैं कि वे अपने इस साहस को बढ़ायें नहीं। अगर वे देश का भला करना चाहें, तो खुद अपना काम धीरे- धीरे कम कर सकते हैं। वे खुद पुराने, प्रौढ़, पवित्र चरखे देश के हजारों घरों में दाखिल कर सकते हैं और लोगों का बुना हुआ कपड़ा लेकर उसे बेच सकते हैं। अगर वे ऐसा न करें तो भी लोग खुद मशीनों का कपड़ा इस्तेमाल करना बन्द कर सकते हैं।

प्रश्न- यह तो कपड़े के बारे में हुआ। लेकिन यंत्र की बनी तो अनेक चीजें हैं। वे चीजें या तो हमें परदेश से लेनी होंगी या ऐसे यंत्र हमारे देश में दाखिल करने होंगे।

उत्तर- सचमुच हमारे देव (मूर्तियाँ) भी जर्मनी के यंत्रों में बनकर आते हैं; तो फिर दियासलाई या आलपिन से लेकर काँच के झाड़-फानूस की तो बात ही क्या? मेरा अपना जवाब तो एक ही है। जब ये सब चीजें यंत्र से नहीं बनती थीं तब हिन्दुस्तान क्या करता था? वैसा ही वह आज भी कर सकता है। जब तक हम हाथ से आलपिन नहीं बनायेंगे तब तक उसके बिना हम अपना काम चला लेंगे। झाड़-फानूस को आग लगा देंगे। मिट्टी के दीये मे तेल डालकर और हमारे खेत में पैदा हुई रूई की बत्ती बनाकर दीया जलायेंगे। ऐसा करने से हमारी आँखें (खराब होने से) बचेंगी, पैसे बचेंगे और हम स्वदेशी रहेंगे, बनेंगे और स्वराज्य की धूनी जगायेंगे। यह सारा काम सब लोग एक ही समय में करेंगे या एक ही समय में कुछ लोग यंत्र की सब चीजें छोड़ देंगे, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर यह विचार सही होगा, तो हम हमेशा शोध-खोज करते रहेंगे और हमेशा थोड़ी-थोड़ी चीजें छोड़ते जायेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे, तो दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे। पहले तो यह विचार जड़ पकड़े यह जरूरी है; बादमें उसके मुताबिक काम होगा।

क्रमश: ...

मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भारी पड़ती गुटबाजी

सिद्धार्थ शंकर गौतम

मध्य प्रदेश में मतदान के लिए 20 दिन का समय ही बचा है। 17 नवंबर को यहां नयी विधानसभा के लिए वोट डाले जाऐंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों को सारी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकनी चाहिए थी लेकिन मतदाता तक पहुंचने की बजाय कांग्रेस अलग ही संघर्ष में उलझी हुई हैं। प्रत्याशियों का अपनी पार्टी में विरोध अब सीमायें लांघने लगा है। कांग्रेस में कई सीटों पर अधिकृत प्रत्याशियों का विरोध वरिष्ठ नेताओं के पुतले फूंकने से लेकर कथित कपड़े फाड़ने तक पहुंच चुका है।

भोपाल के पास बैरसिया विधानसभा में टिकट वितरण से असंतुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष दिग्विजय सिंह का न केवल पुतला ही फूंका बल्कि वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले के बाहर बैठकर उनकी सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के समर्थक थे किंतु बैरसिया में टिकट कमलनाथ कोटे में गया और दिग्विजय सिंह कुछ नहीं कर पाए इसलिए कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा।

इसी प्रकार दतिया की सेवड़ा विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी वर्तमान विधायक घनश्याम सिंह के टिकट के विरोध में दिग्विजय सिंह का पुतला फूंक दिया। ऐसा ही हाल प्रदेश की लगभग 20 विधानसभाओं में है जहां कांग्रेस प्रत्याशी का पुरजोर विरोध पार्टी की नाक में दम किए हुए है। विरोध मात्र पुतला फूंकने तक होता तो भी ठीक था। राजनीति में प्रतीकात्मक विरोध का यह तरीका लंबे समय से नाराजगी प्रकट करने का माध्यम है किंतु नौबत कपड़े फाड़ने तक की आ गई है।

कमलनाथ असंतुष्ट कांग्रेसियों से स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि गुस्सा निकालना है तो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ ने भले ही यह बात व्यंग अथवा हास-परिहास में कही हो किंतु राजनीतिक पंडित जानते हैं कि इसके गहरे निहितार्थ हैं। कांग्रेस में वर्तमान में ऐसा कोई नेता नहीं है जो रुठे नेताओं को मना सके। मध्य प्रदेश के दोनों कांग्रेस नेताओं का कद राष्ट्रीय है अत: इनके बीच अदावत को सुलझाने में नेतृत्व भी असफल रहा है।

दरअसल, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमल दल में जाने से अनायास ही कई गुटों में विभाजित कांग्रेस में मात्र दो ही गुट बचे हैं। शेष सभी गुटों ने कमलनाथ अथवा दिग्विजय सिंह की सरपरस्ती में आना ही उचित समझा है। अब चाहे कमलनाथ हों या दिग्विजय सिंह, दोनों बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में लगे रहे ताकि प्रदेश में उनकी सियासी ताकत कम न हो।

दोनों नेता लाख एकजुटता का राग अलापें किंतु दोनों ही अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां देर-सवेर उनकी राजनीति पर विराम लगेगा। ऐसे में दोनों ही नेता अपने-अपने पुत्रों को स्थापित करना चाहते हैं और यह तभी संभव है जब उनके समर्थक भी उनके पुत्रों को स्वीकार करें। बस, कांग्रेस में इसी जद्दोजहद में कई विधानसभा सीटों पर टिकट वितरण गलत हो गया। टिकट मिलने के सर्वे के पैमाने को चाटुकारिता ने हरा दिया। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अपने बेटे सांसद नकुल नाथ से करवा दिया वहीं दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह का दखल मालवा और मध्य भारत के टिकट वितरण में बढ़ता गया।

अब आलम यह है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी और अरुण यादव सहित अजय सिंह, विवेक तनखा जैसे बड़े नेता स्वयं को उपेक्षित मान रहे हैं। इनमें से मात्र अजय सिंह को ही टिकट मिला है जिसे दिग्विजय सिंह के कोटे का समझिए। इन सबमें, अहम सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इतना असहाय हो चुका है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मंशा समझने के बाद भी मौन है? क्या दोनों ही नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भांति कांग्रेस नेतृत्व को कुछ नहीं समझ रहे? यह सवाल इसलिए क्योंकि नकुल नाथ का प्रत्याशियों का ऐलान तो सीधे-सीधे नेतृत्व को चुनौती ही है। हालांकि असंतोष के बढ़ने के चलते 7 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदले हैं किंतु अब उनका भी विरोध होने लगा है। परिस्थिति जस की तस है।

टिकट वितरण को लेकर भाजपा में भी कम असंतोष नहीं है। यहां भी कई विधानसभाओं में जूतम-पैजार हो चुकी है किंतु कांग्रेस और भाजपा में सबसे बड़ा अंतर अनुशासन का है। भाजपा में जहां डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्रीय मंत्रियों की फौज के साथ सह-संगठन मंत्री शिवप्रकाश ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं कांग्रेस में असंतोष की खाई इस कदर चौड़ी हो चुकी है कि चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कमलनाथ-दिग्विजय सिंह की तल्खी पर मीडिया को मैनेज करना पड़ा। जबकि दोनों में हुई तू-तू, मैं-मैं को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा।

उत्तराखंड में एनसीईआरटी की सिफारिशें होंगी लागू, 'इंडिया' की जगह लेगा 'भारत', विरासत को भी किया जाएगा शामिलउत्तराखंड में एनसीईआरटी की सिफारिशें होंगी लागू, 'इंडिया' की जगह लेगा 'भारत', विरासत को भी किया जाएगा शामिल

कमलनाथ यह प्रचारित करते हैं कि इस बार वे प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएंगे किंतु यदि बगावत, असंतोष और पुत्रमोह का जंजाल बना रहा तो उनका सत्तासीन होना असंभव ही है। वैसे भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का इतिहास मुख्यमंत्रियों को लेकर असमंजस भरा ही रहा है फिर भले ही वो कैलाश नाथ काटजू हों या श्यामाचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह हों या दिग्विजय सिंह, सभी अचानक ही मुख्यमंत्री बने जबकि इनके स्थान पर नाम किसी और का चला था।

कांग्रेस की गुटबाजी का इतिहास रहा है कि जो स्वयं को उच्च पद हेतु प्रायोजित करता है, उसके पैरों तले राजनीतिक जमीन सरका दी जाती है। यदि इस बार कांग्रेस सरकार बनाने लायक संख्या बल प्राप्त भी कर लेती है तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, यह दिग्विजय सिंह और उनके सुपुत्र तय करेंगे क्योंकि जीते हुए अधिकांश विधायक उन्हीं के कोटे के होंगे। और यदि वे तय न कर पाए तो कमलनाथ ऐसे कांटों के ताज को धारण करेंगे जिसमें भाजपा के कांटों से अधिक उनकी अपनी पार्टी के त्रिशूल होंगे।

चंबल से ग्वालियर तक की सीटें तय करेंगी एमपी की सियासत की तासीर!

आशीष तिवारी

चंबल का नाम सुनते ही जहन में बगावत करने वाले डाकुओं की तस्वीर उभर कर सामने आती है। ग्वालियर का नाम आते ही राजा रजवाड़ों और सियासत की एक वो तस्वीर उभरती है, जिसने एमपी से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में बड़ी पहचान बनाई। लेकिन मध्यप्रदेश की सियासत में ग्वालियर और चंबल दोनों वह क्षेत्र हैं, जो यहां की सियासत को एक नया मोड़ भी देते हैं और एक तासीर भी पैदा करते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा का इसी ग्वालियर और चंबल संभाग ने सूपड़ा साफ कर दिया था। फिलहाल मध्यप्रदेश की सियासत में मजबूत दावेदारी रखने वाले ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार बड़े-बड़े नेताओं की अग्नि परीक्षा भी हो रही है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। मध्यप्रदेश के सियासी जानकारों का कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा का सूपड़ा साफ किया और फिर यहां पर हुई नेताओं की बगावत ने सियासत को बदल दिया, वह बताने को काफी है कि यहां की सियासत की तासीर क्या है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अमित तोमर कहते हैं कि 2018 के चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका इस इलाके से लगा था। यहां के आठ जिलों की 34 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में सात सीटें ही आई थीं। जबकि 26 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। वह कहते हैं कि जिस तरीके से इस इलाके में भाजपा के बढ़ रहे विजय रथ को रोक दिया था। ठीक उसी तरह इस क्षेत्र में हुई सियासी बगावत के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सीन कर दिया। राजनीतिक विश्लेषक बीएस अवस्थी कहते हैं कि 2018 के चुनावों के परिणाम के बाद हुई बगावत को भाजपा बहुत गंभीरता से ले रही है। उनका कहना है कि यही वजह है कि इस चुनाव में बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने सियासी मैदान में उतारा है। अगर चंबल और ग्वालियर संभाग को ही देखे तो केंद्रीय कृषि मंत्री और कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर समेत मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और शिवराज की कैबिनेट में मंत्री प्रद्युम्न सिंह ग्वालियर से सियासी ताल ठोक कर राजनीति के सभी मोहरे दुरुस्त करने में लगे हैं। अवस्थी कहते हैं कि यह चुनाव बीते तीन चुनाव की तुलना में सबसे अलग चुनाव माना जा रहा है। इसके पीछे उनके कई तर्क भी हैं। उसमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण तर्क यही है कि तीन बार की सरकार की एंटी इनकंबेंसी भी है और पिछले चुनाव में हुई सियासी उलटफेर की नाराजगी भी। हालांकि उनका कहना है कि भाजपा ने पिछले चुनाव में हुई अपनी हार को देखते हुए इस बार बड़े मजबूत चेहरे इस इलाके में उतारे हैं। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश यादव कहते हैं कि चंबल और ग्वालियर का सियासी समीकरण ही ऐसा है कि भोपाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी को बनाने और बिगड़ने का पूरा दमखम रखता है। इन दोनों संभाग के आठ जिलों भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर, शिवपुरी, गुना अशोकनगर समेत दतिया में 34 विधानसभा की सीटें हैं। वह कहते हैं कि इस इलाके की सियासत में जमीनी मुद्दे और किसानों के मुद्दे हमेशा से हावी रहे हैं। पीछे उनका तर्क है कि यहां की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उनका कहना है कि इस इलाके में दलितों की ज्यादा आबादी होने के चलते यहां पर सियासी समीकरण भी इस लिहाज से तय होते हैं। फिलहाल ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार बड़े सियासी मुद्दों में 2018 के चुनाव में हुई सियासत की बगावत का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वह कहते हैं यह नाराजगी उन नेताओं के खिलाफ सबसे ज्यादा है जो बगावत में शामिल थे। यादव कहते हैं कि चुनाव में जितनी प्रतिष्ठा भाजपा की दांव पर लगी है, उतनी ही कांग्रेस की भी लगी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों या नरोत्तम मिश्रा या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनका कहना है कि यह पहला चुनाव है जब सिंधिया परिवार से सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ सबसे बड़ी प्रतिष्ठा ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी इसमें लग गई है। क्योंकि पिछले चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से बगावत का बिगुल फूंकने के बाद यहां की राजनीति में न सिर्फ तूफान आया, बल्कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था।

चुनौती भाजपा को, जोर आजमाइश विपक्षी गठबंधन इंडिया में!

राजकुमार सिंह

दो दर्जन से भी ज्यादा विपक्षी दलों ने जब 18 जुलाई को बेंगलुरु में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) नाम से नए गठबंधन का ऐलान किया था तो उद्देश्य अगले लोकसभा चुनाव में केंद्रीय सत्ता से भाजपा सरकार की विदाई बताया था। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा था कि भाजपा को हराने के लिए वे त्याग करने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि यही राष्ट्रीय हित का तकाजा है। लेकिन, पहली बड़ी चुनावी परीक्षा में ही वे वायदे और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। नवंबर में हो रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम-से-कम चार दल कांग्रेस, आप, सपा और जदयू परस्पर ताल ठोंक रहे हैं। तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दल बीआरएस और मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में हैं। ये दल विपक्षी गठबंधन में शामिल भी नहीं हैं। इसलिए इन राज्यों में तो विपक्षी गठबंधन में परस्पर टकराव की संभावना नहीं, लेकिन शेष तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये दल आपस में टकराते दिख रहे हैं। इन राज्यों में मुख्य रूप से सत्ता के लिए संघर्ष भाजपा और कांग्रेस के बीच होता रहा है, पर गठबंधन के बावजूद आप, सपा और जदयू भी जनाधार के बहाने या फिर विस्तार की आकांक्षा के सहारे उम्मीदवार उतार रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में चुनावी टकराव की स्थिति इसलिए भी बनी है, क्योंकि आपस में सीट बंटवारा नहीं हो पाया। गठबंधन बनने के बाद कहा गया था कि सब मिल कर चलेंगे और सीट बंटवारे समेत तमाम मुद्दों को प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा, पर वैसा हो नहीं पाया। इसका एक कारण कांग्रेस की रणनीति भी है। इसी साल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की सत्ता भाजपा से छीन लेने के बाद कांग्रेस को लगता है कि देश का मूड उसके अनुकूल है। यह भी कि अगर वह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2018 का करिश्मा दोहरा पाई, जब उसने भाजपा से सत्ता छीन ली थी, तब गठबंधन में वह निर्णायक भूमिका में होगी। गठबंधन के अन्य दल कांग्रेस की इस टालमटोल से आहत हैं और आशंकित भी। इसीलिए आप ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी। आप का इरादा राजस्थान में भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने का है। तय है कि आप अंतत: कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाएगी, जिसका लाभ भाजपा को मिलेगा। सपा ने कांग्रेस पर सीट बंटवारे में धोखा देने का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश में लगभग दो दर्जन सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि उन्हें छह सीटों का आश्वासन दिया गया था, लेकिन एक भी सीट नहीं छोड़ी गई। ध्यान रहे कि पिछली बार सपा एक सीट जीती भी थी। कुछ क्षेत्रों में सीमित असरवाली सपा नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाएगी। इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। आप और सपा के बाद अब जदयू ने भी मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है।

योगी मंत्रिमंडल विस्तार की बाट जोहते ओपी राजभर

राजेंद्र कुमार

योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की आस में विजयदशमी भी बीत गई है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय नहीं हुई। ऐसे में अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के सामने मंत्रिमंडल विस्तार की बाट जोहते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ओम प्रकाश राजभर जो ओपी राजभर के नाम से देशभर में जाने जाते हैं। योगी सरकार में मंत्री बनने की तमन्ना के चलते ओपी राजभर समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव से नाता तोड़कर बीते सितंबर में वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(एनडीए) में शामिल हुए थे। तब से वह योगी सरकार में मंत्री बनाए जाने को लेकर कई दावे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई है।

बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेताओं ने उन्हे इस मामले में अब बयानबाजी ना करने की सलाह दी है। यानी कि उनके मंत्री बनाने का मामला अब दो एक महीने टल गया है। हालांकि मंत्री बनाए जाने की पक्की संभावनाओं के चलते ही बीते सितंबर में ओपी राजभर ने यह एलान किया था कि उन्हे जल्दी ही योगी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इस विश्वास के बाद ही उन्होंने सपा को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके लिए ओपी राजभर सूबे में पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों व वंचितों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सपा सरकार की नाकामियों को बताने में जुट गए हैं। जिसके तहत वह सपा पर पिछड़ों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं।

पिछड़ों खासकर दलितों के बीच जाकर वह गेस्ट हाउस कांड (जून 1995 हो हुए) का जिक्र करते हुए सपा नेताओं द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ किए गए

दुर्व्यवहार और नौकरी में प्रमोशन में एससी-एसटी के आरक्षण को खत्म करने के मामले को उठा रहे है। इसी प्रकार वह सपा सरकार के दौरान दलितों और अति पिछड़ों की अनदेखी से जुड़े कई प्रकरणों का जिक्र कर सपा को दलित और पिछड़े समाज का विरोधी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ओपी राजभर को उम्मीद थी कि सपा के खिलाफ उनके द्वारा चलाया जा रहा अभियान उन्हे भाजपा का हितैषी साबित करेगा और जल्दी ही उन्हे योगी सरकार में जगह भी मिल जाएगी।

ओपी राजभर ही यह मंशा पूरी भी हो जाती अगर घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की हार ना हुई होती। दारा सिंह चौहान की जीत का दावा ओपी राजभर ने भाजपा के बड़े नेताओं से किया था और उन्हे जीतने के लिए 15 दिन वह घोषी में कैंप भी किए थे। घोसी विधानसभा सीट पर 50 हजार से अधिक राजभर मतदाता हैं और ओपी राजभर ने दावा किया था कि यह समूचा वोट दारा सिंह चौहान को ही मिलेगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं और 50 हजार से अधिक वोटों से दारा सिंह चौहान की हार हुई। इसके बाद भी ओपी राजभर ने यह दावा किया जल्दी ही वह योगी सरकार में मंत्री बनेंगे। जबकि सभी को पता था कि सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हे अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के इच्छुक नहीं है क्योंकि बीते विधानसभा चुनावों के पहले जब उन्होंने योगी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा के साथ जाने का फैसला किया था, तब उन्होने भाजपा और योगी सरकार की आलोचना की थी। उनके इस कृत से सीएम योगी अभी भी भूले नहीं है, इसलिए उन्होने पार्टी के शीर्ष नेताओं के संकेत के बाद भी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में रुचि नहीं दिखाई है। जबकि दस दिन पहले ओपी राजभर ने विजयदशमी के पहले योगी सरकार में मंत्री बनाए जाने की बात मीडियाकर्मियों से कही थी।

ऐसे में विजयदशमी के बीतते ही उनके मंत्री ना बनाए जाने की चर्चा फिर होने लगी है और अब यह कहा जा रहा है ओपी राजभर के पास अब मंत्री बनने के लिए इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सूबे में राजनीति के जानकारों का कहना है कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक दो तरह की राय है। एक राय है कि योगी सरकार के जिन मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाना है उन्हें अभी से मंत्री पद से मुक्त कर चुनाव की तैयारी में लगा दिया जाए।

दूसरी राय है कि फिलहाल सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर, मऊ से चुनाव हारे दारा सिंह चौहान सहित कुछ अन्य चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। उसके बाद दूसरा विस्तार लोकसभा चुनाव के बाद कर लिया जाए। ऐसी चर्चाओं को लेकर भाजपा नेताओं का कहना है कि सीएम योगी अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोच नहीं रहे हैं। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के चुनाव परिणाम आने के बाद ही इस मामले में वह कोई फैसला लेंगे। तब तक ओपी राजभर को मंत्रिमंडल विस्तार की बांट जोहनी पड़ेगी।

नौकरशाहों की राजनीति में बढ़ती रुचि सेवा से प्रेरित तो कतई नहीं है

ललित गर्ग

पांच राज्यों के विधानसभा एवं अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अनेक प्रशासनिक अधिकारी राजनीति में आने के लिये अपने पदों से इस्तिफा दे रहे हैं। इन प्रशासनिक अधिकारियों को नौकरशाही की तुलना में राजनीति इतनी लुभावनी क्यों लग रही है, क्यों राजनीति के प्रति इन नौकरशाहों में आकर्षण बढ़ रहा है? इन्हीं प्रश्नों के बीच अहम प्रश्न है कि आईएएस अधिकारी वी.के. पांडियन द्वारा स्वैच्छिक रिटायरमेंट एवं मध्य प्रदेश में डिप्टी कलक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर होने की खबरे एवं उनके राजनीतिक दलों से जुड़कर चुनाव लड़ना लोकतंत्र को किस मोड़ पर ले जायेंगे। इनके अतिरिक्त भी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, आईएफएस, डॉक्टर, प्रोफेसर आईपीएस अफसर आदि अनेक नौकरशाह राजनीति में अपना भविष्य आजमाने को तत्पर हैं। लोकशाही और नौकरशाही निश्चय ही लोकतंत्र के दो प्रमुख स्तम्भ हैं। दोनों के कंधों पर लोकतंत्र की सफलता एवं राष्ट्र-निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देशहित का जज्बा ही दिखाना है तो क्या नौकरशाह में यह संभव नहीं है? ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का जीवन अनेकों विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरा रहता है। इन दोनों की सारी नीतियों में, सारे निर्णयों में, व्यवहारों में, कथनों में गहरा विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित है। यही कारण है कि सत्य एवं संभावनाएं खोजने से भी नहीं मिलती, इनका व्यवहार दोगला हो गया है। दोहरे मापदण्ड अपनाने से उनकी हर नीति, हर निर्णय समाधानों से ज्यादा समस्याएं पैदा कर रहे हैं। पांडियन और निशा के इन फैसलों से कई सवाल खड़े हुए हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

नौकरशाहों की राजनीति की ओर बढ़ने की होड़ सेवा प्रेरित तो कतई नहीं है। यह अधिक से और अधिक पाने की भूख है जो नौकरशाही की तरह राजनीति को भी अधिक भ्रष्ट ही करेगी। यह सर्वविदित है कि देश की प्रशासनिक संस्थाएं किस कदर साख एवं समझ के संकट से जूझ रही हैं? उन पर राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने का आरोप निराधार नहीं है। यह न तो देश के हित में है और न लोकतंत्र के। ऐसे में, पांडियन और निशा जैसे उदाहरणों से नौकरशाही की विश्वसनीयता को और खरोंचें आएंगी, राजनीति भी साफ-सुथरी रहने की संभावनाएं धूमिल होगी। इसलिए, देश को सचमुच प्रशासनिक सुधार के साथ उसे मजबूत करने के लिये प्रशासनिक अधिकारी अपने पदों पर रहते हुए देश-निर्माण की जिम्मेदारी निभाये, यह ज्यादा जरूरी है। हमारा संविधान तय मानदंडों के तहत अपने हरेक नागरिक को अवसर की स्वतंत्रता देता है, और इस लिहाज से अफसरों के राजनीति में आने में कुछ गलत नहीं है, मगर इन दिनों जिस तरह नौकरशाहों में राजनेताओं के कृपापात्र बनने और पुरस्कृत होने की प्रवृत्ति गहराती जा रही है, उसमें पांडियन एवं निशा जैसे तरक्की पसन्द, महत्वाकांक्षी एवं लालची अफसरों का राजनीतिक में घूसपैठ का मुद्दा अन्य नौकरशाहों को भी सत्ताधीशों से सांठ-गांठ के लिए प्रेरित करेगा। इससे प्रशासनिक क्षेत्र में अजीब ऊहापोह एवं अस्थिरता बनेगी। जरूरत इस बात की है कि विधायिका,

कार्यपालिका और न्यायपालिका से संविधान ने जो उम्मीदें पाली हैं, उन पर वे खरी उतर सकें और हम आदर्श लोकतंत्र के रूप में दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सके।मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां उभार पर हैं। इस बार वहां चुनावी घमासान में अपना भविष्य आजमाने वाले अफसरों की सूची पर नजर डालें तो निशा बांद्रे डिप्टी कलेक्टर सबसे ऊपर हैं, रिटायर्ड आईपीएस अफसर एमपी वरकडे के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की संभावना है। वरद मूर्ति मिश्रा आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं, सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। वी.के. बाथम रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इनके भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। बी. चंद्रशेखर, किरण अहिरवार, अजिता वाजपेयी पांडे, हीरालाल त्रिवेदी, पन्नालाल सोलंकी, पवन जैन, गाजी राम मीणा, आजाद सिंह डबास आदि अनेक अफसरों के नाम हैं जिनके अब सक्रिय रूप से राजनीति में आने एवं चुनाव लड़ने की संभावना है। अफसरों का राजनीति से बढ़ रहा मोह कोई नया नहीं है। राज्यों से लेकर केन्द्र की राजनीति में इन प्रशासनिक अधिकारियों का वर्चस्व रहा है और दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन प्रशासनिक अधिकारियों के दोनों हाथों में रेवड़ियां हैं- पहले नौकरशाह के रूप में और अब राजनेता के रूप में।

आजादी के अमृतकाल में पहुंचने तक विभिन्न राजनीतिक दलों में ऐसे नौकरशाह रहे हैं जिन्होंने उच्च सरकारी पदों को छोड़ उच्च राजनीतिक पदों पर रहे हैं। नटवर सिंह, मणिशंकर अय्यर, मीरा कुमार, अजीत जोगी, यशवंत सिन्हा आदि पूर्व में मंत्री रहे हैं तो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी सरकार में अश्विनी वैष्णव (आईएएस 1994-बैच), केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं और उनके पास रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे तीन बड़े विभाग हैं। जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया, इसी तरह, हरदीप सिंह पुरी के पास शहरी विकास और पेट्रोलियम विभाग हैं, जबकि आर.के. सिंह बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं और अर्जुन राम मेघवाल (आईएएस 1999-बैच) कानून और न्याय, संसदीय मामलों और संस्कृति राज्य मंत्री (एमओएस) हैं। मेघवाल राजस्थान बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। वहीं, सोम प्रकाश (आईएएस 1988-बैच) वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। पूर्व सिविल सेवक भी अब प्रमुख भाजपा की संगठनात्मक भूमिकाओं में कदम रख रहे हैं जो पहले कैडरों के लिए आरक्षित थे। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के रूप में के. अन्नामलाई (आईपीएस 2011-बैच) की नियुक्ति देखी जा सकती है। दूसरा उदाहरण रायपुर के पूर्व कलेक्टर ओ.पी. चौधरी (आईएएस 2005-बैच) का है। उन्हें 2022 में छत्तीसगढ़ में भाजपा का महासचिव नियुक्त किया गया था।

वैसे, यह कोई पहली बार नहीं है कि प्रशासनिक क्षेत्र के लोग सीधे राजनीति में कूद पड़े हैं, आजादी के वक्त से ही विभिन्न क्षेत्रों के लोग सरकार एवं राजनीति का हिस्सा बनते रहे हैं और देश-समाज को इसका लाभ भी मिला है। मगर वे अपने-अपने क्षेत्र के माहिर लोग होते थे और उन्हें किसी बड़े राजनेता या राजनीतिक दल के करीबी होने मात्र का लाभ नहीं मिल जाता था। बल्कि उनकी काबिलियत ने सरकारों को बाध्य किया कि वे सरकार में आये और अपनी प्रतिभा-कौशल का लाभ देश को दे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में सत्ताधीशों और नौकरशाहों के गठजोड़ ने न सिर्फ राजनीति को विद्रूप किया है, बल्कि शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें इसके कारण गहरी हुई हैं। ऐसे में, निशा एवं पांडियन जैसे लोगों के राजनीति में सक्रिय होने से क्या वर्षों से जनसेवा में जुटे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं होगा? क्या नौकरशाहों की वरीयता लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप है? क्या यह राजनीति में एक नये तरह के असंतोष एवं विद्रोह को नहीं पनपायेगी?पांडियन और निशा का राजनीति में आने का फैसला जनसेवा से प्रेरित है या लोभ एवं महत्वाकांक्षाओं की परिणति? यदि उन्हें राजनीति में इतनी ही दिलचस्पी थी, तो प्रशासन में इतने वर्ष खर्च क्यों किए? क्यों नहीं प्रशासन में रहते हुए देश के लिये कुछ अनूठा करके दिखाया। राजनेताओं से भी अधिक अपेक्षाएं नौकरशाहों से की जाती है, यदि वे चाहते तो जनापेक्षाओं खरे उतरते।

जिम करने वाले सितारों पर कंगना रणौत ने किया कटाक्ष, पूछा- वहां करते ही क्या हैं?

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत फिल्मों के साथ-साथ बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। कंगना रणौत जल्द ही दर्शकों के लिए फिल्म 'तेजस' लेकर आ रही है, जिसको लेकर वह खबरों में हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान अपनी आगामी फिल्म तेजस का प्रचार करते वक्त अभिनेत्री ने उन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर कटाक्ष किया, जो किसी भी भूमिका की तैयारी के लिए जिम जाना शुरू कर देते हैं।

जिम करने वाले अभिनेताओं पर किया कटाक्ष

मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना रणौत ने कहा, 'हमारे अभिनेता और अभिनेत्रियां फिटनेस को लेकर जुनूनी हो गए हैं। वे अपना दिन शीशों को देखकर बिताते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह भूल जाते हैं कि वे मॉडल या पॉप स्टार नहीं हैं। शारीरिक दिखावे पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका को खो रहे हैं।'

कंगना ने कभी नहीं लिया वर्कआउट का सहारा

कंगना रणौत ने अभिनेताओं के जिम जाने पर सवाल उठाया और कहा, 'भूमिका या तैयारी की आवश्यकता के बावजूद वे हमेशा पहले जिम क्यों जाते हैं? मुझे नहीं पता कि वे जिम में क्या ही करते हैं? मुझे कभी ऐसी कोई भूमिका नहीं मिली। यहां तक कि तेजस में लड़ाकू प्रशिक्षण आवश्यक था, लेकिन मैंने कभी जिम वर्कआउट का सहारा नहीं लिया। यह अलग तरह का प्रशिक्षण है। यह काफी अजीब है कि अधिकांश अभिनेता प्रत्येक भूमिका की तैयारी के लिए जिम जाते हैं।

विधु विनोद की फिल्म से भिड़ेगी 'तेजस'

कंगना रणौत के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री फिल्म 'तेजस' की रिलीज को लेकर व्यस्त हैं। तेजस में कंगना आईएएफ अधिकारी तेजस गिल की भूमिका नजर आएंगी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की टक्कर विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित '12वीं फेल' से भिड़ेगी।

विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म आईपीएस मनोज शर्मा की कहानी पर आधारित है, जिसका किरदार विक्रांत मैसी ने निभाया है, जो 12वीं कक्षा में फेल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और यूपीएससी परीक्षा में सफल रहे।

'यह एक बड़ी जिम्मेदारी है...', इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकन बनने पर बोले राजकुमार राव

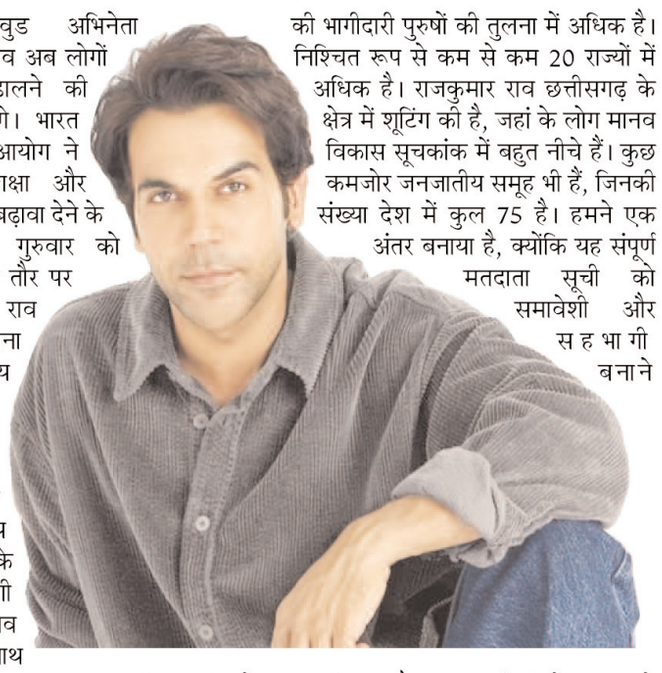

बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव अब लोगों से वोट डालने की अपील करेंगे। भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता शिक्षा और मतदान को बढ़ावा देने के लिए आज गुरुवार को आधिकारिक तौर पर राजकुमार राव को अपना 'राष्ट्रीय आइकन' घोषित किया। अभिनेता ने आज राष्ट्रीय राजधानी के आकाशवाणी भवन में चुनाव निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया, जिसके बाद अब वह आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बन चुके हैं।

नई जिम्मेदारी के लिए अपना उत्साह साझा करते हुए राजकुमार राव ने कहा, ₹यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह एक बड़ा सम्मान है। ईमानदारी से कहूं तो मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत प्रभावित हूं और हां, अब लोगों को प्रेरित करना एक जिम्मेदारी है। लोग, विशेषकर हमारे युवा बाहर आएं और मतदान करें। यह लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, इसलिए हम सभी के लिए बाहर जाना और अपना वोट डालना बहुत महत्वपूर्ण है।''

इससे पहले, कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, एक बार जब आप मतदान करके और चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र में न्यायाधीश बन जाते हैं तो यह जुनून आपके कार्यों में भी आएगा। आप लोकतंत्र की ताकत को समझेंगे। आज मतदान में हमारी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक है। निश्चित रूप से कम से कम 20 राज्यों में अधिक है। राजकुमार राव छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शूटिंग की है, जहां के लोग मानव विकास सूचकांक में बहुत नीचे हैं। कुछ कमजोर जनजातीय समूह भी हैं, जिनकी संख्या देश में कुल 75 है। हमने एक अंतर बनाया है, क्योंकि यह संपूर्ण मतदाता सूची को समावेशी और सहभागी बनाने का हिस्सा है। हम सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को मतदाताओं के रूप में शामिल करेंगे।

राजकुमार राव ने सभी से मतदान की अपील करते हुए कहा कि आज मैं यहां किसी फिल्म का प्रचार करने, किसी सीरीज का प्रचार करने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं यहां लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी मतदान को बढ़ावा देने के लिए खड़ा हूं। मुझ पर विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि वोट डालने पर आपको जो अनुभूति होती है, वह आपको कहीं और अनुभव नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में भागीदारी की भावना, सरकार बनाने में भागीदारी की भावना। यह सबसे अच्छा एहसास है और आप इसे चूकना नहीं चाहेंगे। मैं आप सभी से आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया यह संदेश फैलाएं कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम जाएं और मतदान करें, क्योंकि हमारे देश के नागरिकों के रूप में लोकतंत्र में यह आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है।

सुभाष घई की शादी की सालगिरह में साथ दिखे संजय दत्त-माधुरी दीक्षित

'खलनायक 2' की चर्चा तेज

बॉलीवुड सुपरस्टार माधुरी दीक्षित और संजय दत्त अभिनीत फिल्म 'खलनायक' आज भी दर्शकों को काफी पसंद है। सुभाष घई की प्रतिष्ठित फिल्म को 30 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दर्शकों के लिए आज भी यह फिल्म यादगार है। सुभाष घई और मुक्ता घई ने हाल ही में अपनी शादी की सालगिरह मनाई, जिसमें फिल्म की पूरी स्टार कास्ट नजर आई। 'खलनायक' की कास्ट को साथ देखकर फैंस के बीच 'खलनायक 2' की चर्चा तेज हो गई है।

माधुरी दीक्षित ने साझा की तस्वीरें

माधुरी दीक्षित ने इस पार्टी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिनमें संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, सुभाष घई और उनकी पत्नी मुक्ता घई साथ में नजर आ रही हैं। इस मौके पर माधुरी के पति डॉक्टर श्रीराम नेने भी मौजूद रहे। माधुरी ने जो पोस्ट साझा की उसकी पहली तस्वीर में माधुरी अपने पति श्रीराम नेने और सुभाष घई के साथ बालकनी में पोज देती नजर आईं।

बेहद खूबसूरत दिखीं माधुरी दीक्षित

इस दौरान ब्लैक और व्हाइट आउटफिट में माधुरी दीक्षित बेहद खूबसूरत नजर आईं। तस्वीर में सुभाष घई के घर से समुद्र के शानदार नजारे की झलक देखने को मिल रही है। अभिनेत्री ने तस्वीरें साझा कर लिखा, 'यह वह कंपनी है जो शाम बनाती है। सुभाष घई और मुक्ता घई को शादी की सालगिरह की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।'

'खलनायक' के सीक्वल की उठी मांग

इन तस्वीरों को देखकर फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। 'खलनायक' की स्टार कास्ट को एक साथ देखकर फैंस अब खलनायक के सीक्वल की मांग कर रहे हैं। एक प्रशंसक ने कमेंट कर लिखा, 'मुझे लगता है कलनायक 2 आने वाली है।' वहीं, सुभाष घई ने संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के साथ बातचीत करते हुए एक तस्वीर साझा कर कैप्शन में लिखा, '1990 के दशक की तरह दिल से दिल की बात करना और हंसना अद्भुत है। हमने अपने घर पर 45वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर अपने नायक और खलनायक संजय ड्यूटी और जैकी श्रॉफ जैसे अच्छे दोस्तों के साथ खूब हंसी-मजाक किया।'

'वह मेरे साथ काम नहीं करेंगी', पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ काम करने पर राज कुंद्रा की प्रतिक्रिया

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी अपनी पत्नी की तरह एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। फिल्म 'यूटी 69' में वह अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 'यूटी 69' के ट्रेलर ने फैंस के बीच फिल्म देखने का उत्साह और बढ़ा दिया है। राज कुंद्रा

से हाल ही में फिल्म के प्रचार के दौरान शिल्पा शेट्टी के साथ फिल्म में काम करने को लेकर सवाल किया गया, जिसका उन्होंने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया है।

राज कुंद्रा ने पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ किसी फिल्म में काम करने के सवाल पर कहा, 'मैं एक न्यूकमर हूं। ये ए-लिस्ट एक्टर मेरे साथ काम नहीं करेंगे।' इसके साथ ही राज ने बताया कि वह हमेशा से ही बॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित थे। उन्होंने बताया कि उनकी भाषा पंजाबी है। उन्होंने फिल्मों से ही हिंदी सीखी है।

इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि जब वह 18 वर्ष के थे तब उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे एक्टिंग स्कूल में भी पढ़ाई की थी। अपनी अपकमिंग फिल्म UT69 का ट्रेलर उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे को भी दिखाया। उन्होंने ट्रेलर देखने के बाद उनकी तारीफ की और कहा कि उन्हें उनकी एक्टिंग स्किल्स पर भरोसा है। बता दें कि डायरेक्टर शाहनवाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म की कहानी राज कुंद्रा के आर्थर रोड जेल में बिताए 63 दिनों पर आधरित है। राज कुंद्रा कि फिल्म इस साल तीन नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। यह फिल्म राज कुंद्रा के 'एडल्ट फिल्म स्कैंडल' पर हुई गिरफ्तारी की कहानी पर आधारित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म के जरिए राज कुंद्रा अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देते नजर आएंगे।

फिर धमाल मचाने को तैयार सूर्या-सुधा कोंगारा की जोड़ी

तमिल सुपरस्टार्स की लिस्ट में सूर्या का नाम जरूर शामिल किया जाता है। अब तक वह कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लोगों का दिल जीत चुके हैं। उनकी बहुत सी फिल्में हिंदी में रीमेक भी की जा चुकी हैं। अभिनेता को सोरारई पोटरू के लिए काफी ज्यादा प्रशंसा मिली थी। अब वह फिल्म इस फिल्म के निर्देशक सुधा कोंगारा के साथ एक फिल्म के लिए फिर से जुड़ गए हैं।

इस फिल्म का फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। अभिनेता की आगामी फिल्म के मेकर्स ने गुरुवार को एक 44 सेकंड का वीडियो जारी किया, जिसका अस्थायी नाम सूर्या 43 है। फिल्म में उनके दुलकर सलमान और नाजरिया और विजय वर्मा भी महत्वपूर्ण किरदारों में दिखेंगे।

फिल्म की पहली बड़ी खूबी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रोडक्शन हाउस 2डी एंटरटेनमेंट ने सूर्या 43 के मुख्य कलाकारों को 'देसी' ताकतवर और मजबूत' बताया। पीरियड एक्शन ड्रामा कही जाने वाली सुधा कोंगारा की इस फिल्म में जीवी प्रकाश का संगीत होगा।

मेकर्स ने जैसे ही वीडियो जारी किया, इस पर प्रशंसक जमकर कमेंट करने लगे। कई फैंस ने इस फिल्म को अभी से मेगा-ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया। बुहत से लोगों ने एक्टर निर्देशक की जोड़ी की खूब तारीफ की। एक यूजर ने फर्स्ट लुक प्रोमो में इस्तेमाल किए गए बैकग्राउंड म्यूजिक की सराहना की और लिखा, ₹बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है।₹ एक अन्य यूजर ने लिखा, ''इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।'' इसके अलावा बहुत से यूजर्स इस पोस्ट पर फायर इमोजी शेयर कर रहे हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो सूर्या इन दिनों अपनी बहुप्रतिक्षित फिल्म कांगुवा को लेकर चर्चा में हैं। सिरुथई सिवन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को बड़े बजट में तैयार किया जा रहा है। हाल ही में यह जानकारी सामने आई थी कि फिल्म के थाईलैंड शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली गई है।

तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू को लेकर उत्साहित हैं विजय वर्मा, पोस्ट साझा कर जताई खुशी

अभिनेता विजय वर्मा बॉलीवुड के बाद अब तमिल सिनेमा में अपने अभिनय का जलवा बिखेरते नजर आएंगे। जल्द ही उन्हें 'सूर्या 43' में देखा जा सकेगा। यह विजय की पहली तमिल फिल्म है, जिसमें वह सूर्या शिवकुमार और दुलकर सलमान के साथ नजर आएंगे। अपनी पहली तमिल फिल्म को लेकर विजय वर्मा बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी खुशी साझा की है।

बता दें कि यह फिल्म तमिल सुपरस्टार सूर्या की 43वीं फिल्म है, इसलिए फिलहाल इसे अस्थाई रूप से 'सूर्या 43' कहा जा रहा है। इसका निर्देशन सुधा कोंगारा कर रहे हैं। हाल ही में विजय ने इस फिल्म का अनाउंसमेंट मोशन पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, 'मेरी पहली तमिल फिल्म....इससे बेहतर टीम नहीं हो सकती। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं'।

इसके अलावा विजय वर्मा ने आगे लिखा, 'बेहद प्रतिभाशाली लोगों के साथ 'सूर्या 43' का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं। इसे शानदार बनाने की कोशिशों में जुटे हैं'। विजय वर्मा ने जैसे ही अपनी इस नई फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया, यूजर्स ने कमेंट की झड़ी लगा दी। साथ ही इंडस्ट्री के तमाम लोग भी विजय को बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'तमिल सिनेमा इंडस्ट्री में आपका स्वागत है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'साउथ में स्वागत है।' एक ने लिखा, 'यह तो बेस्ट न्यूज है। आप, सूर्या और दुलकर...वो भी एक साथ...जरूर धमाल होने वाला है।'

इन प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे विजय

बता दें कि सूर्या शिवकुमार ने गुरुवार को अपने नए प्रोजेक्ट 'सूर्या 43' का एलान किया था। फिल्म में विजय, सूर्या और दुलकर सलमान के साथ-साथ नजरिया नजीम भी अहम रोल में हैं। विजय के अलावा दुलकर ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस प्रोजेक्ट में काम करने की खुशी जताई। बता दें कि सूर्या इससे पहले वर्ष 2020 में आई और सुधा कोंगारा के निर्देशन में बनी 'सोरारई पोटरू' फिल्म में भी काम कर चुके हैं। इसके लिए सूर्या को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिला। विजय वर्मा के वर्क फ्रंट की बात करें तो आखिरी बार वह फिल्म 'जाने जां' में करीना कपूर के साथ नजर आए थे। अब वह जल्द ही होमी अदजानिया की 'मर्डर मुबारक' में नजर आएंगे। इसमें सारा अली खान, करिश्मा कपूर, डिंपल कपाड़िया और जान्हवी कपूर भी नजर आएंगी। इसके अलावा 'मिर्जापुर 3' भी विजय की झोली में है।

अंजना-नानी के रिश्ते की नींव बनी दोस्ती एक्टर को ऐसे मिली उनकी मोहब्बत

बॉलीवुड की खूबसूरत फिल्मों में शुमार 'कुछ कुछ होता है' से सुपरस्टार शाहरुख खान का डायलॉग 'प्यार दोस्ती है...' आज भी लोगों के कानों में गूंजता है। यह डायलॉग लोगों को तब-तब याद आता है, जब वह अपने दिलों जान से प्यारे दोस्तों को दिल हार बैठते हैं। लेकिन आज हम इस डायलॉग को याद कर न तो शाहरुख खान का जिक्र करेंगे और न ही उनकी लव स्टोरी का। आज हमें यह डायलॉग साउथ सुपरस्टार नानी और उनकी खूबसूरत पत्नी अंजना येलावर्ति की लव स्टोरी की याद दिला रहा है। जी हां, नानी और अंजना की लव स्टोरी का मूल उनकी गहरी दोस्ती ही है। तो चलिए आज दोनों की 11वीं शादी की सालगिरह पर जानते हैं उनकी दोस्ती से भरी प्यारी लव स्टोरी के बारे में...

अंजना के लिए नानी का इंतजार

साउथ सिनेमा में पिछले कई वर्षों से राज कर रहे सुपरस्टार नानी की दुनिया दीवानी है, लेकिन उनके दिलों दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ अंजना येलावर्ति पर राज रहा है। नानी और अंजना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं। दोनों ने अपनी जिंदगी के 11 साल एक-दूसरे के साथ बेहतरीन ढंग से गुजारे हैं और उनकी प्रेम कहानी भी उतनी ही प्यारी और फिल्मी है। फिल्मों में हीरोइन का दिल अपनी प्यारी सी मुस्कान से जीतने वाले नानी को असल जिंदगी में अंजना को

जीतने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा था।

ऐसे पड़ी नानी और अंजना के प्यार की नींव

अंजना से नानी की पहली मुलाकात उन दिनों में हुई थी जब उनका फिल्मी दुनिया से कोई नाता नहीं था। जी हां, नानी की मुलाकात अंजना से उस वक्त हुई थी, जब अभिनेता विजाग में एक आरजे के रूप में काम किया करते थे। इस पहली मुलाकात में दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि वह एक दिन जिंदगी साथ गुजारने की कसमें खाएंगे। हालांकि, नानी और अंजना के प्यार की नींव उस दिन पड़ी जब दोनों की दोस्ती हुई। पहली मुलाकात के बाद दोनों जल्द ही दोस्त बन गए थे। धीरे-धीरे दोस्त के रूप में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और नानी-अंजना की यही दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल गई।

पांच साल तक डेटिंग करने के बाद लिया शादी का फैसला

दोस्ती की सीढ़ी चढ़ने के प्यार जब नानी और अंजना ने प्यार की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया तब तक वे दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे थे। एक-दूसरे के लिए वह समझ, प्यार और सम्मान आने वाले पांच वर्षों में और भी गहरा हो गया था। पांच वर्षों तक डेट करने के बाद नानी और अंजना समझ गए थे कि वह एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसे में दोनों ने अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया था। जैसे-जैसे नानी और अंजना का रिश्ता गंभीर होता गया, वैसे-वैसे दोनों ने अपने परिवारों को करीब लाने की कोशिश शुरू कर दी थी।

हमेशा के लिए एक हुए दोनों

नानी और अंजना ने अपने परिवारों की मंजूरी पाने के लिए खूब कोशिश की और आखिरकार दोनों की कोशिशें रंग लाईं। इसके बाद नानी और अंजना आखिरकार 27 अक्तूबर 2012 को हमेशा-हमेशा के लिए एक हो गए। दोनों की शादी में करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल हुए थे। शादी के करीब पांच साल बाद दोनों के घर नन्हे शहजादे का जन्म हुआ। नानी और अंजना आज भी एक-दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं, जितना पहले किया करते थे। अंजना ने नानी को उनके संघर्षपूर्ण दिनों में बहुत सपोर्ट किया।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री ने 51 हजार लोगों को सौंपा नियुक्ति पत्र

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोज़गार मेले के दौरान 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किये गये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेले की ये यात्रा इस महीनें एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीनें में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। तबसे निरंतर केंद्र शासित और भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी 50 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। दिवाली में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50 हजार युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

कांग्रेस पर जमकर बरसे बीआरएस नेता केटी रामाराव

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना मंत्री केटी रामाराव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश में कोई असली सफेद हाथी है तो वह ग्रैंड ओल्ड पार्टी है क्योंकि लोगों ने सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के कुशासन का खामियाजा भुगता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों ने सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के कुशासन और दुस्साहस का खामियाजा भुगता है। तो असली सफेद हाथी, चाहे कोई कुछ भी मानना चाहे, मेरी व्यक्तिगत आस्था तो कांग्रेस है। और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, 1948 में आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से, यह अभी भी वहां है। इसलिए बहुत उपद्रव है। तेलंगाना के मंत्री की टिप्पणी राज्य में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आई है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है। राज्य में इस बार मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच होने जा रहा है।

राजस्थान के लिए आरएलपी ने दस उम्मीदवारों की घोषणा की

जयपुर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है जिसके तहत पार्टी के संयोजक, सांसद हनुमान बेनीवाल विधानसभा की खींवसर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की सूची के अनुसार भोपालगढ़ से मौजूदा विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता से विधायक इंदिरा देवी बावरी चुनाव लड़ेंगी। खींवसर से इस समय सांसद के भाई नारायण बेनीवाल विधायक हैं। पार्टी ने खींवसर से उन्हें टिकट नहीं दिया है। इस सूची में उनका नाम भी नहीं है। पार्टी ने इसके अलावा परबतसर से लछाराम बडारड़ा, कोलायत से रेवतराम पंवार, सहाड़ा से बद्रीलाल जाट, बायतू से उम्मेदाराम बेनीवाल, सरदारशहर से लालचंद मूंड, सांगानेर से महेश सैनी और जोधपुर शहर से डॉ. अजय त्रिवेदी को टिकट दिया है। उल्लेखनीय है कि हनुमान बेनीवाल ने 2018 का विधानसभा चुनाव खींवसर से जीता था।

महुआ मोइत्रा की मांग को एथिक्स कमेटी ने किया खारिज

नईदिल्ली। लोकसभा आचार समिति ने शनिवार को तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को कैश-फॉर-क्वेरी मामले में 31 अक्टूबर के बजाय 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा। समिति ने कहा कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। मोइत्रा ने लोकसभा की आचार समिति को लिखा, जो उनके खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों की जांच कर रही है और 31 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने में असमर्थता जताई और कहा कि वह 5 नवंबर के बाद ही उपलब्ध होंगी। पैनल के अध्यक्ष विनोद सोनकर को लिखे अपने पत्र में मोइत्रा ने कहा कि वह अपमानजनक आरोपों के खिलाफ शारीरिक रूप से उपस्थित होने और अपना बचाव पेश करने के लिए उत्सुकता से उत्सुक हैं और उन्हें व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जिरह करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हीरानंदानी को समिति के सामने पेश होना चाहिए।

महुआ मोइत्रा पर निशिकांत दुबे ने फिर साधा निशाना

नईदिल्ली। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पूछताछ के लिए नकद आरोपों पर चल रहे विवाद के बीच, शिकायतकर्ता और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि मामले में गवाह दर्शन हीरानंदानी को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मोइत्रा का जिक्र करते हुए कहा कि दुबई दीदी बिजनेसमैन के संपर्क में हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सूचना के अनुसार दर्शन हीरानंदानी व दुबई दीदी (सांसद) सम्पर्क में हैं। गवाह को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष को कारवाई करनी चाहिए। एक और पोस्ट में भाजपा सांसद ने लिखा कि दुबई दीदी ने कुछ लोगों को जिरह के लिए कहा,लोकसभा के नियमों खासकर कौल-शकधर किताब के पेज 246 के तहत विटनेस कोर्ट, कचहरी, हल्ला गुल्ला से संरक्षित है। खाता ना बही दुबई दीदी जो कहे वही सही।

मध्यप्रदेश में बोलीं प्रियंका गांधी, कांग्रेस को मिलेगा भारी बहुमत

मोदी सरकार सिर्फ इवेंटबाजी कर रही है : प्रियंका

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का राज्य का दौरा जारी है। प्रियंका गांधी शनिवार को मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ दमोह जिले में विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जैसे-जैसे समय बीतता है, राजनीतिक नेताओं से हमारी उम्मीदें कम होती जाती हैं। अब जब मैं लोगों से सरकार या नेताओं से उनकी अपेक्षाओं के बारे में पूछती हूं, तो उत्तर एक ही होता है कि उनका जीवन संघर्ष से भरा है। उनकी उम्मीदें न्यूनतम हैं। वे सड़क, पानी, बिजली और महंगाई से राहत चाहते हैं। स्थिति अजीब हो गई है। अवसरों की कमी के कारण बहुत अधिक पलायन होता है।

प्रियंका ने कहा कि हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में जातिगत जनगणना कि गई है जिसके अनुसार वहां 84% जनता एसटी, एससी और ओबीसी है। लेकिन अगर आप नौकरियों में बड़े-बड़े पदों को देखेंगे कि इन समुदायों का प्रतिनिधित्व क्या है तो आप पाएंगे कि इतना प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, भाजपा के लोग मौन हो जाते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण दिया, इसलिए आज गांव-गांव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बड़े बदलाव के लिए तैयार है। 225 महीने के शासन में 250 घोटाले करने वाली भ्रष्ट भाजपा सरकार जा रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस आ रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के मौके बेहद कम हैं, इसलिए यहां पलायन बहुत हो रहा है। पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सिर्फ 21 नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि आज कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। आपने आजीवन देश की सेवा की, इसलिए पेंशन आपका हक बनता है। लेकिन मोदी सरकार कहती है- इसके लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पैसे नहीं हैं... तो अडानी जैसे उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं?

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महिला आरक्षण को लेकर सिर्फ इवेंटबाजी कर रही है। वे देश को गुमराह कर रहे हैं कि हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण आने वाले 10 साल में लागू ही नहीं होगा।

स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि गाजा में संघर्ष-विराम के लिए मतदान से दूर रहा भारत

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शनिवार को कहा कि वह इससे स्तब्ध और शर्मिंदा हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष-विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि जब मानवता के हर कानून को ध्वस्त कर दिया गया है, तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया, जिसमें इज़रायल-हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय संघर्ष-विराम का आह्वान किया गया था। प्रियंका ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए अपने पोस्ट में महात्मा गांधी के उस कथन का उल्लेख किया कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। उन्होंने कहा, मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष-विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। प्रियंका ने कहा, हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी। इन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया।

प्रियंका के मध्यप्रदेश दौरे पर सीएम शिवराज सिंह का वार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के चुनावी राज्य के दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की झूठ की दुकान खुल रही है। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हैं और आज उन्होंने दमोह से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और उम्मीदवार अजय टंडन के समर्थन में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी के दौरे के बारे में बोलते हुए सीएम चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है। प्रियंका गांधी फिर यहां आ रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें भगवान राम और राम मंदिर से क्या दिक्कत है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि राम मंदिर के होर्डिंग्स हटाए जाएं और महाकाल महालोक के पोस्टर हटाए जाएं। अपनी रैली में प्रियंका गांधी ने चौहान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों का जीवन अभी भी संघर्षपूर्ण है। राज्य में राम मंदिर के पोस्टर लगाए जाने पर कांग्रेस के विरोध पर भी शिवराज चौहान ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप (कांग्रेस) किसी समय भगवान राम को काल्पनिक व्यक्ति कहते थे। कांग्रेस कहती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख सामने आ गई है, 22 जनवरी। भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। पूरे राज्य में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का स्वागत करने वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य भाजपा इकाई के प्रमुख नेताओं की तस्वीरें हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए शहर में लगे होर्डिंग्स के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराएगी। इस बीच सीएम चौहान ने आगे उज्जैन के महाकाल महालोक निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने (कांग्रेस) फर्जी आरोप लगाए और पूछा कि आपको महाकाल महालोक से क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा, महाकाल महलोक का निर्माण कराया गया और आपने फर्जी आरोप (भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए) लगा दिये।

कृषि मंत्री थे तो किसानों के लिए क्या किया

प्रधानमंत्री मोदी के तंज पर शरद पवार ने दिया जवाब

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी के आरोप का जवाब दिया है, जिन्होंने शिरडी में एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान पूछा था कि जब वह देश के कृषि मंत्री थे तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया था। प्रधान मंत्री ने अहमदनगर के शिरडी शहर में एक रैली के दौरान कहा था, हम अच्छे इरादों के साथ किसानों को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं लेकिन महाराष्ट्र में कुछ लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्रीय कृषि मंत्री थे वर्षों से। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं लेकिन उन्होंने किसानों के लिए क्या किया?

शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने संवैधानिक पद के दायरे में रहते हुए टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पद है। एक प्रधानमंत्री को अपने संवैधानिक कद को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों निशाना बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह इस तथ्य के कारण है कि उन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि पीएम ने मुझ पर जो भी बयान दिया है, मैं पीएम पद की महत्ता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए उस पर जवाब दूंगा। जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार (2004-14) थी तब शरद पवार कृषि मंत्री थे। यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार पर परोक्ष हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार सक्रिय रूप से किसानों को सशक्त बना रही है, वहीं महाराष्ट्र में कुछ लोग किसानों का प्रतिनिधित्व करने की आड़ में राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। शरद पवार ने यह भी दावा किया कि सत्ता खोने के डर ने पीएम को ऐसी टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया होगा। उन्होंने कहा कि वह (पीएम) शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए गए थे, वहां शरद पवार के दर्शन करने की क्या जरूरत थी। देशभर की तस्वीर देखें तो ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है या फिर उनकी सरकार दूसरे दलों में तोड़फोड़ के बाद आई है। और जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां वे कमजोर स्थिति में हैं। शायद इसी कमजोरी और सत्ता खोने के डर ने उन्हें (पीएम) ऐसे बयान देने के लिए मजबूर किया होगा।

कल तक मोदी खुद को शरद पवार का चेला बताते थे : संजय राउत

उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजित पवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार के सामने शरद पवार की बुराई हो रही थी और इसके मजे पीएम मोदी व भाजपा नेता ले रहे थे, तो खुद को गौरवान्वित मराठा कहने वाले अजित को मंच से चले जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो लोग बुराई के मजे लेते हैं। उनका यही काम है। आज शरद पवार की बुराई कर रहे, कल बालासाहेब ठाकरे की बुराई करेंगे। उनका सिर्फ मतलब से नाता है। मतलब निकल जाता है तो छोड़ देते हैं। राउत ने कहा कि कल तक शरद पवार की मदद से कई काम हो रहे थे। पीएम मोदी खुद को उनका चेला बताते थे। शरद पवार को कृषि और समाजिक क्षेत्र में ज्ञान रखने और योगदान के लिए पद्म विभूषण सम्मान भी मिल चुका है। तब नहीं लगा कि उस नेता ने क्या किया है।

खेल
प्रमुख समाचार

विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला आज

नईदिल्ली। भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में जहां लगातार पांच मैच जीतकर खिताब की सबसे प्रबल दावेदार साबित हुई है तो पिछले चैम्पियन इंग्लैंड के सामने अब सेमीफाइनल में दौड़ में बने रहने का प्रश्न है और ऐसे में दोनों टीमें आज रविवार को आमने सामने होंगी तो मेजबान का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है।

रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने लगातार पांच मैच जीते हैं जबकि सफेद गेंद के क्रिकेट की नई परिभाषा गढने वाले इंग्लैंड के सामने टूर्नामेंट में अस्तित्व बनाये रखने की लड़ाई है। भारत को इस मैच में हरफनमौला हार्दिक पंड्या की कमी खलेगी। स्पिनरों की मददगार पिच पर आम तौर पर शार्दुल ठाकुर की जगह रविचंद्रन अश्विन को उतारा जाता लेकिन पंड्या की गैर मौजूदगी में टीम प्रबंधन को पांच गेंदबाजों के साथ ही उतरना पड़ सकता है। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का चयन तो तय है। तीसरे स्पिनर के तौर पर अश्विन को उतारने के लिये मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज में से एक को बाहर करना होगा। शमी ने धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच विकेट लिये लिहाजा उन्हें अब बाहर रखना मुश्किल होगा। रोहित शर्मा से अच्छी शुरूआत मिलने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। टीम लक्ष्य का पीछा करने में महारथी साबित हुई है। पंड्या की गैर मौजूदगी में छठे नंबर पर सूर्यकुमार यादव उतर सकते हैं। धर्मशाला में श्रेयस अय्यर के विकेट से शॉर्टपिच गेंदों के सामने उनकी कमजोरी पर फिर चर्चा होने लगी है। वह अपने आलोचकों को बल्ले से जवाब देना चाहेंगे। डेंगू के कारण पहले दो मैचों से बाहर रहे शुभमन गिल से भी एक बड़ी पारी का इंतजार है। वहीं लखनऊ में विराट कोहली रिकॉर्ड की बराबरी करने वाला 49वां शतक भी जमा सकते हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी

मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को शुक्रवार को एक ईमेल पर जान से मारने की धमकी मिली। आरोपियों ने उद्योगपति को 20 करोड़ रुपये न देने पर गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि मुंबई के गामदेवी थाने में आईपीसी की धारा 387 और 506 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, धमकी भरे ईमेल में लिखा गया है कि अगर तुम हमें 20 करोड़ रुपये नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, हमारे पास भारत के सबसे अच्छे शूटर हैं। भेजने वाले की पहचान शादाब खान के रूप में हुई। खतरे का पता चलने पर, अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत अधिकारियों को सतर्क कर दिया। मुंबई की गामदेवी पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई और अज्ञात प्रेषक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ईमेल के स्रोत और धमकी के पीछे वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू की गई।

टीएसीएल कंपनी का स्टॉक पिछले 5 माह में 142% उछला

नई दिल्ली। टैलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स (टीएसीएल) के शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 20 प्रतिशत के अपर सर्किट पर बंद हुए। इसी के साथ कंपनी के शेयर 251.45 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए। ऑटो एंसिलरी कंपनी का स्टॉक 1:5 के अनुपात में स्टॉक विभाजन के लिए पूर्व-दिनांकित हो गया है, यानी 10 रुपये अंकित मूल्य के 1 स्टॉक को 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के 5 शेयरों में विभाजित किया गया है। टैलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के शेयर ने 11 अगस्त को छूए अपने पिछले हाई लेवल 232.59 रुपये (स्टॉक स्प्लिट के अनुसार समायोजित) को पार कर लिया। कुल मिलाकर लगभग 10 लाख इक्विटी शेयरों की अदला-बदली हुई और एनएसई तथा बीएसई पर लगभग 1 लाख शेयरों के खरीद ऑर्डर लंबित थे।

आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 34% बढ़ी

नई दिल्ली। आकलन वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) में 500 करोड़ रुपये से अधिक की सकल कुल आय के साथ 589 करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया। दूसरी ओर, लगभग 2.1 करोड़ करदाताओं ने कर का भुगतान किया, लेकिन 2021-22 में रिटर्न दाखिल नहीं किया। आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में यह बात सामने आई है। आकलन वर्ष 2021-22 में 500 करोड़ रुपये से अधिक का रिटर्न दाखिल करने वाली 441 इकाइयों की तुलना में यह संख्या लगभग 34 प्रतिशत बढ़ी है। आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 1.6 करोड़ करदाताओं ने कर का भुगतान किया, लेकिन आकलन वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया। इस दौरान करीब 6.7 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए। प्रत्यक्ष करों में आय और निगम कर शामिल हैं, जिसमें 554 में से 589 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपये से अधिक की सकल कुल आय का रिटर्न दाखिल किया है।

एनपीएस से बाहर निकलने के नियमों में बदलाव

नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा है कि निकासी या योजना से बाहर निकलने के दौरान अंशधारक के बैंक खातों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कोष का समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के लिए अब तत्काल बैंक खाते का सत्यापन कराना अनिवार्य है। यह बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पेनी-ड्रॉप मेथड के जरिए होगा। पीएफआरडीए के 25 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र के अनुसार, निकास/निकासी अनुरोधों को संसाधित करने और ग्राहक बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के लिए नाम मिलान के साथ सफल पेनी-ड्रॉप सत्यापन आवश्यक है। यदि सीआरए पेनी ड्रॉप की पुष्टि करने में असमर्थ है, तो पेंशन नियामक ने कहा कि ग्राहक के बैंक खाते की जानकारी में निकास/निकासी या परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वैश्विक पूंजी में बदलाव भारत के लिए अवसर..

आकाश प्रकाश

हाल ही में मुझे दुनिया भर के परिसंपत्ति आवंटकों और मुद्रा प्रबंधकों से मिलने का अवसर मिला। वे दीर्घकालिक स्तर पर काम करने वाली पूंजी का प्रबंधन करते हैं ताकि जोखिम समायोजन वाला प्रतिफल हासिल हो सके। हमने भारत, उभरते बाजारों और दुनिया को लेकर उनके नजरिये पर बातचीत की। इस बातचीत से निकले कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

1. पिछली बैठकों में कई ऐसे निवेश नीतिकार थे जो चीन से नाउम्मीद नहीं हुए थे। कई को लग रहा था कि चीन भूराजनीतिक और आर्थिक मामलों में चक्रीय गिरावट का शिकार है। एक वर्ष पहले कुछ निवेशक सस्ती दरों पर चीन में निवेश करना चाह रहे थे। अब मिजाज एकदम अलग हैं। चीन के मामले में हर किसी की सीमाएं है।

यह निर्णय निवेश टीमों द्वारा नहीं लिया जाता है बल्कि संभावित सरकारी नियमन से जुड़ा है ताकि जोखिम से बचा जा सके। चीन का मूल्यांकन चाहे जितना आकर्षक हो, अधिकांश निवेशक वहां निवेश नहीं करना चाहेंगे। अगर चीन के बाजारों में आगे और गिरावट आती है तो बचे हुए निवेशकों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कुछ एक परिवार वाले कारोबार अवश्य अपवाद रहे जो बोर्ड-ट्रस्टी व्यवस्था से संचालित नहीं होते हैं। उनका प्रदर्शन विरोधाभासी है। अधिकांश संस्थानों ने जहां चीन में अपना निवेश आधा से कम कर दिया, वहीं चीन के पूंजी बाजारों के कमजोर प्रदर्शन के चलते आवंटन में भी कमी आ रही है। कई लोगों ने अपने सूचीबद्ध शेयर बेच दिए हैं लेकिन निजी परिसंपत्तियों के नकदी संकट में उलझे हुए हैं। उनका पैसा वापस मिलने में कई वर्षों का समय लग जाएगा क्योंकि अधिकांश

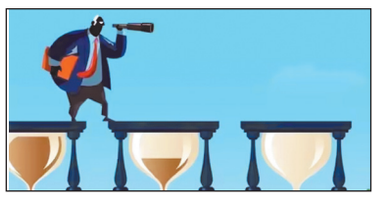

चीनी निजी फंड जानते हैं कि वे अमेरिका से नई पूंजी नहीं जुटा सकते। ऐसे में वे भी किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। चीन की वित्तीय परिसंपत्तियों से दूर संतुलन कायम करने के लिए स्पष्ट अनुदेश है लेकिन इसके पूर्ण क्रियान्वयन में तीन से पांच वर्ष का समय लगेगा।

2. मैं जिन संस्थानों से मिला उनमें से कई पर नकदी का अल्पकालिक दबाव था। उनके यहां निजी निवेश का एक्सपोजर अधिक था और वे संभावित वितरण में पीछे थे। यह स्थिति अस्थायी है और इसमें 12 से 18 महीनों में सुधार हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि टिकटॉक की चीनी मालिक कंपनी बाइटडांस में सभी संस्थानों का काफी निवेश था। नकदी का दबाव चीन से भारत की ओर पूंजी की गति को भी प्रभावित कर रहा है और चीन से निकाली जाने वाली राशि फिलहाल अल्पावधि की नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा रही है।

3. तमाम आवंटकों में भारत को लेकर रुचि कहीं अधिक है जबकि ऐतिहासिक रूप से ऐसा नहीं रहा है। भारत में निवेश परिदृश्य को प्रासंगिक बनाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग निरंतर काम कर रहे थे। एक तथ्य यह है कि अगले पांच वर्षों में किसी अन्य देश में स्थिर वृहद आर्थिक संकेतकों के साथ 6-7 फीसदी की आर्थिक वृद्धि की काबिलियत नहीं नजर आई। इसके साथ ही हर चर्चा में 12-15 फीसदी आय वृद्धि की संभावना जाहिर की गई। कई अवसरों पर भारत की उच्च गुणवत्तायुक्त प्रदर्शन क्षमता का भी उल्लेख किया गया। अभी भी ?सक्रिय शेयरों के चयन को ही आगे जाने की राह माना गया। माना जा रहा था कि कोई अन्य विकल्प न होने की भावना काम कर रही थी क्योंकि कई अन्य बड़े उभरते बाजार वाले देश चुनौतियों का सामना कर रहे थे। घरेलू निवेशकों के उभरते मजबूत आधार पर भी नजर रखी गई और इसे सकारात्मक माना गया। कई लोगों ने कहा कि भारतीय बाजार मजबूत है और अक्टूबर 2021 से 2022 के मध्य तक उसने 40 अरब डॉलर की संस्थागत विदेशी निवेश की बिकवाली को घरेलू पूंजी के सहारे झेल लिया। घरेलू रुझानों को सराहा गया और इसे दीर्घकालिक संभावनाओं के प्रमुख संकेतक के रूप में देखा गया।

4. भारत को लेकर प्राथमिक चिंता मूल्यांकन की है। अब भारत अमेरिका के साथ दुनिया का सबसे महंगा बाजार है।

छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला

माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा। चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जोगी कांग्रेस, हमर राज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समेत कई दल अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। पिछली बार जोगी कांग्रेस और बसपा मिलकर चुनाव लडे थे और दोनों पार्टियां सात सीटें जीती थीं। इस बार दोनों अलग -अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार जोगी कांग्रेस और बसपा ही कही-कहीं अपना प्रभाव दिखा सकती है , बाकी दलों का कोई मतलब नहीं रहेगा। राज्य में असल मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होना है। अब कौन बाजी जीतता है, यह तो तीन दिसंबर को ही पता चलेगा।

कही-सुनी

रवि भोई

जुगाड़ वाले कांग्रेस प्रत्याशी

कहते हैं कांग्रेस के एक प्रत्याशी राज्य के नेताओं के न चाहते हुए अपनी मनपसंद सीट से टिकट पाने में कामयाब रहे। चर्चा है कि ये नेता छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन से जुगाड़ जमाकर अपने लिए टिकट की व्यवस्था कर ली। खबर है कि राज्य के बड़े नेता इस सीट से एक महिला को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन हाईकमान के कोटे से टिकट मिलने के कारण यहां के नेताओं की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद राज्य के नेताओं को महिला नेता को दूसरी सीट से उम्मीदवार बनाना पड़ा। अजय माकन के सहारे नैया पार करने वाले नेता की तरह सभी किस्मत वाले नहीं निकले। कुछ लोग तो टिकट के लिए दिल्ली में बैठ गए थे। सीट को पेंडिग में डाल भी दिया गया, लेकिन आखिरी समय निराशा ही हाथ लगी।

भूपेश बघेल ने चला ब्रम्हास्त्र

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता में आने पर फिर कर्जा माफ़ी की घोषणा कर भाजपा को मुसीबत में डाल दिया है। भाजपा के नेता अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत कुछ होने की बात तो कर रहे हैं,पर भूपेश बघेल के ब्रम्हास्त्र का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में धान और किसान ने कांग्रेस को निर्णायक बढ़त दिलाई थी। इस बार भी भाजपा के कुछ करने के पहले भूपेश बघेल ने किसानों के सामने पिटारा रख दिया है। 2018 में सत्ता में आने पर कांग्रेस ने तत्काल वादे पूरे किए थे, इस कारण किसानों को भूपेश बघेल की घोषणा पर भरोसा हो चला है। अब लोगों को भाजपा के घोषणा पत्र का इंतजार है।

भारी पड़ गई समधी से दोस्ती

चर्चा है कि भाजपा के कद्दावर नेता गौरीशंकर अग्रवाल को अपने समधी रामगोपाल अग्रवाल से मधुरता भारी पड़ गई। कहा जा रहा है कि गौरीशंकर अग्रवाल का नाम रामगोपाल अग्रवाल से नहीं जुड़ता तो उन्हें भी कसडोल से टिकट मिल जाती। रामगोपाल अग्रवाल ईडी के निशाने पर आ गए हैं। कसडोल सीट को पेंडिंग में डाला गया था और आखिरी समय पर फैसला लिया गया, वहां से धनीराम धीवर को प्रत्याशी बनाया गया है। वैसे भी भाजपा ने चार अग्रवाल को टिकट दिया है। रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, बसना से संपत अग्रवाल और अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल उम्मीदवार बनाए गए हैं।

किस्मत वाले प्रत्याशी

रायपुर उत्तर के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप जुनेजा और बेलतरा के भाजपा प्रत्याशी सुशांत शुक्ला को किस्मत वाला प्रत्याशी माना जा रहा है। दोनों के नाम का फैसला आखिरी समय हुआ। कुलदीप जुनेजा को चुनाव की घोषणा के

कुछ दिन ही पहले दोबारा हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, इस कारण माना जा रहा था कि कुलदीप का पत्ता साफ होने वाला है , लेकिन कहते हैं न दो कि लड़ाई में तीसरे को फायदा हो जाता है , ऐसा ही कुलदीप के साथ हुआ। दो ताकतवर लोग लड़े और कुलदीप के नाम पर मुहर लग गई। कहते हैं ऐसा कुछ बेलतरा में सुशांत के साथ हुआ। सुशांत को प्रवक्ता बना देने से मानकर चला जा रहा था कि सुशांत रेस से बाहर हो गए ,लेकिन आखिरी समय भाग्य ने साथ दिया और प्रत्याशी घोषित हो गए।

चुनाव मैदान में नहीं दिखेंगे अमित

चुनाव की घोषणा से पहले पाटन जाकर ताल ठोंकने वाले जोगी कांग्रेस के नेता अमित जोगी इस बार भी चुनाव मैदान में नजर नहीं आएंगे। बताते हैं पिछली बार की तरह अमित रणनीतिकार रहेंगे और चुनाव का संचालन करेंगे। जोगी कांग्रेस ने 60 से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जोगी परिवार से डॉ रेणु जोगी और ऋचा जोगी मैदान में हैं। ऐसे में किसी को चुनावी रणनीति के लिए

मैदान से बाहर रहना ही होगा। अब देखते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस क्या करामात दिखाती है। वैसे अजीत जोगी के निधन के बाद अमित ने मरवाही से लड़ने की कोशिश की , पर जाति के पेंच में उलझ गए।

भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार

पहले चरण के मतदान में करीब 10 दिन बचे हैं , लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने अब तक अपना -अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है। लोगों को अब दोनों प्रमुख दलों के घोषणा पत्र का इंतजार है। 2018 में कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद चुनावी माहौल बदला था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्जा माफ़ी की घोषणा कर दी है, ऐसे में यह मुद्दा तो उनके घोषणा पत्र में रहने वाला ही है। किसान न्याय योजना की राशि बढ़ने की भी चर्चा है। इसके अलावा तेंदूपत्ता का बोनस बढाकर वनवासियों को लुभाने की बात हो रही है। भाजपा भी किसान और वनवासियों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

भूपेश है तो भरोसा है का दौर आने से पहले खत्म हुआ: श्रीवास्तव

- , हम नहीं चरण दास महंत का बयान इसका संकेत : संजय श्रीवास्तव
- ,परदेसिया सांसदों को राहुल गांधी कम से कम टूर पर ही सही छत्तीसगढ़ लेकर तो आए:संजय श्रीवास्तव
- ,भाजपा ने जारी किया कांग्रेस के परदेसिया लापता सांसदों का पोस्टर
- ,संजय श्रीवास्तव बोले छत्तीसगढ़ के लोगों का हक मारने वाली कांग्रेस को जनता सबक सिखायेगी

रायपुर। आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस ब्रीफ को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता श्री संजय श्रीवास्तव ने कहा की भूपेश है तो भरोसा का दौर खत्म हो गया ।ये हम नही कांग्रेस नेताओं के बयान बता रहे है ।वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरण दास महंत ने कह दिया कि कांग्रेस का फिलहाल कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लडा जा रहा है अगर सत्ता आई तो दिल्ली में मुख्यमंत्री तय होगा यानी अब कांग्रेस ने बिलकुल साफ कर दिया की उन्हे भूपेश बघेल पर भरोसा नही है।

उससे पहले भी मुख्यमंत्री के कई बार विरोध के बाद भी टी एस सिंहदेव को दिल्ली से आदेश कर उपमुख्यमंत्री बनाया था।

संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ कोटे से राज्यसभा भेजे गए सांसदों के बारे में कहा की वो कहा लापता है ।राहुल गांधी उन्हे छत्तीसगढ़ टूर पर ही ले आते कम से कम जनता अपने राज्यसभा सांसदों के चेहरे तो देख लेती ।संजय श्रीवास्तव ने कहा भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगो का हक मारा है छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगो को राज्यसभा भेजना पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान है और जनता अपना हक मारने वालो को सबक सिखाने जा रही है ।राहुल गांधी बताए उनके ये छत्तीसगढ़ के सांसद कहा लापता है। इसी दौरान प्रदेशनप्रवक्ता संजय श्रीवास्तव और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने लापता राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी करते हुए पूछा ये सांसद कहा लापता है।

भूपेश की खुद की गारंटी नहीं, वे घोषणा पर घोषणा कर रहे: अरुण

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्या वे नई घोषणाएं करने के पहले पिछले चुनाव में की गई अपनी घोषणाओं का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को देंगे? उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया है कि छत्तीसगढ़ में 200 फूड प्रोसेसिंग प्लांट कहां हैं? नक्सल प्रभावित हर पंचायत को 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं मिला? शराब बंदी लागू क्यों नहीं हुई? सभी को चार गैस सिलेंडर मुफ्त में क्यों नहीं मिले? महिलाओं की 1500 की पेंशन कहां है? कर्मचारियों का नियमितीकरण कहां है? छात्रों को 5 साल तक मुफ्त परिवहन क्यों नहीं मिला? बेरोजगारों के 15 हजार करोड़ रुपए कहां गए? न भत्ता दिया न रोजगार दिया। श्री साव ने कहा अब तक 700 से ज्यादा घोषणाएं की जा चुकी हैं। भूपेश बघेल और राहुल गांधी मिलकर घोषणाओं का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने पर आमादा है लेकिन जनता इनके किसी भी वादे पर ऐतबार नहीं कर सकती। क्योंकि 5 साल तक जनता ने कांग्रेस की धोखेबाजी झेली है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव के घोषणा पत्र में करीब 300 वादे किए थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की जनता से कुल मिलाकर 400 के करीब वादे कर चुके हैं। इसके बाद हर रोज घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए कि जब 5 साल पहले किए गए वादे नहीं निभाए तो अब नई-नई घोषणाएं करने का उन्हें नैतिक अधिकार कैसे हैं?

भाजपा की सरकार बनने पर पीएम आवास योजना फिर बहाल करवाएंगे: मूणत

- जनसंवाद से जनता की नब्ज टटोल रहे हैं मूणत, ब्राम्हण समाज के लोगों से मांगा बीजेपी के पक्ष में आशीर्वाद

रायपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश मूणत अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान रायपुर शहर की जनता की भावनाओ और आकांक्षाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। राजेश मूणत ने बताया कि वह रायपुर पश्चिम विधानसभा में अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान मूणत लगातार मोहल्ला विकास समितियों और सामाजिक प्रमुखों की बैठके भी ले रहे हैं। *जनदर्शन के साथ देव दर्शन का लाभ ले रहे मूणत* शनिवार की सुबह प्रात: उठकर अपने निवास में उपस्थित नागरिकों से संवाद कर सर्वप्रथम मंदिरों , गुरुद्वारों में दर्शन लाभ लेकर जनसंपर्क की शुरुवात की। *बैठकों का दौर जारी, ब्राम्हण समाज के लोगों के साथ हुई भेंट* उन्होंने अयप्पा मंदिर दर्शन कर भगवान अयप्पा से विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। सुबह 9:30 बजे उन्होंने निज निवास पर ब्राम्हण समाज के दल

से भेंट की उसके पश्चात सी.ए. प्रोफेशनल ग्रुप के साथ बैठक की उसके पश्चात पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड पार्षद कार्यालय पर बैठक की वहां से माधवराव सप्रे वार्ड खारुन पैलेस पहुंचे ,जहां स्थानीय नागरिकों ने अपने उनका पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया वहां से ठाकुर प्यारेलाल वार्ड , संत रविदास वार्ड और ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड में स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठके की। श्री राजेश मूणत शनिवार शाम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड पहुंचे। जहां उन्होंनेशहनाई गार्डन में सैकड़ो संख्या में उपस्थित ब्राम्हण समाज के लोगों से मुलाकात की। इस बैठक में भाजपा नेत्री मीनल चौबे, प्रभात दुबे समेत कई नेता भी शामिल थे। श्री राजेश मूणत ने ब्राम्हण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों का अभिवादन करते हुए कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि और सरकार सर्वसमाज की भावनाओं को साथ लेकर ही राष्ट्र विकास की दिशा में कार्य कर सकता है। उन्होंने कहा कि ब्राम्हण समाज के लोगों का रायपुर शहर की मूल भावना को जीवित रखने में,इसे बनाने में बड़ा योगदान रहा है। आप एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर रायपुर शहर को कांग्रेस के चंगुल से आज़ाद करने में अपना सहयोग प्रदान करें। इस दौरान आम जनता और खास करके महिलाएं जगह जगह फूल मालाओं और आरती की थालियों से मूणत का स्वागत कर रही है। श्री राजेश मूणत ने बताया कि जनता से मिल रहे अपरिमित प्रेम से जीत के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों का बोध भी हो रहा है ।उन्होंने आगे कहा कि मैने सदैव जन समस्यायों के निदान के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया है, इसे निरंतर जारी रखना मेरी प्राथमिकता है ।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

भाजपा पांचो राज्यो में चुनाव हार रही: बैज

रायपुर। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ में मारे गये ईडी के छापे भाजपा की घबराहट को बताने के लिये पर्याप्त है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हार रही है। इसलिये वह केन्द्रीय एजेंसियो और केन्द्रीय सुरक्षा बलो का दुरूपयोग करना शुरू कर चुकी है। भाजपा तानाशाही और अलोकतांत्रिक गतिविधियों पर उतर आई है। उसके पास कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे नहीं बचे है तो वह ईडी के माध्यम से गलत कार्यवाहियां करवा कर भ्रष्टाचार के भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। बैज ने कहा कि 2014 में केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से प्रमुख विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए जांच एजेंसियों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मोदी सरकार के 8 साल के शासन में 95 फीसदी मामले केवल विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ़ किए गए हैं। जो नेता भाजपा में शामिल हो गये उनके खिलाफ भाजपा ने जांच बंद करवा दिया। नारायण राणे, मुकुल राय, हेमंत बिसवा सरमा, येदुरप्पा, एकनाथ शिंदे जैसे दर्जनों नेता जिनके खिलाफ ई डी, आई टी और सीबीआई की कार्यवाही चल रही थी, बकायदा एफआईआर दर्ज है, भाजपा में शामिल होते ही सदाचारी हो गए सारे आरोपों से मुक्त हो गये ।उन्होंने कहा कि देश में जब से मोदी सरकार बनी है वह केंद्रीय एजेंसियों का मनमाने दुरुपयोग कर रही है।

किसानों की खुशहाली से भाजपा नेता दुखी क्यों हो जाते है: ठाकुर

रायपुर। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा सरकार बनने पर किसानों को कर्ज मुक्त करने और 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा के बाद किसान विरोधी भाजपा के नेताओ को तकलीफ होना शुरू हो गया। पूर्व रमन सरकार के दौरान 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होती थी। भाजपा नेता किस मुंह से 20 क्विंटल धान खरीदी करने की घोषणा पर सवाल उठा रहे हैं? बीते 5 वर्षों में भूपेश सरकार ने प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी किया है। 2500 रु प्रति क्विंटल देने का वादा किया था उसे ज्यादा 2640 रु और 2660 रु खरीदा है। 1 नवंबर से 20 क्विंटल धान की खरीदी लगभग 2800 रु कीमत पर होगी जो भाजपा शासित राज्यों में किसानों को नहीं मिलता है। मोदी सरकार के किसान विरोधी काला कानून का विरोध करने वाले आंदोलनकारी किसानों को भाजपा नेता आतंकवादी, नक्सली, टुकड़े-टुकड़े गैंग, देशद्रोही कहते थे। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की करारी हार में देखते हुए, भाजपा नेता किसानों के हितैषी होने का स्वांग रच रहे हैं। घड़ियाली आंसू बहा रहे है। भाजपा नेताओं के बहरूपिया चरित्र को किसान जानते और पहचानते है। रमन सिंह ने कहा था किसानों को बोनस देने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब होगी इसलिए बोनस नहीं देंगे, धान की कीमत 2100 रु नही देंगे। किसानों का बोनस खाने वाले भाजपा के नेता आज किस मुंह से किसान हितैषी भूपेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।

कांग्रेस केंद्रीय मंत्रियों की शिकायत करेगी : शुक्ला

रायपुर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा राज्य के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की चुनाव आयोग से की गयी शिकायत को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा की खीझ बताया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। इसलिये वह अब अपने हारने के बहानेबाजी की पटकथा लिखना शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में लगी है। प्रदेश भर में अमित शाह, मंडाविया जैसे भाजपा की केंद्र सरकार के मंत्री घूम-घूम कर चुनाव को प्रभावित करने के लिये अपने रसूख का दुरुपयोग कर रहे है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के नेता लगातार राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमका रहे, उनमें भय पैदा करने की कोशिश कर रहे। भाजपा का अधिकारियों को धमकाना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ आपराधिक कृत्य भी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा राज्य के अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग में की गयी शिकायत भी इसी अभियान का हिस्सा है। वे अपने केंद्रीय मंत्री पद का गलत इस्तेमाल कर राज्य के अधिकारियों में भय पैदा कर रहे है। कांग्रेस पार्टी भी भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों के इस आचरण की शिकायत चुनाव आयोग में करेगी।

अरुण साव बतायें सांसद के तौर पर उनकी क्या उपलब्धि रही: वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि झूठ, जुमला, कुशासन और वादाखिलाफी भाजपा के पर्यायवाची बन चुके है। अरूण साव से छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है कि सांसद के तौर पर पिछले साढ़े 4 साल में उनकी क्या उपलब्धि है? भाजपा के 2003, 2008 और 2013 के घोषणा पत्र, रमन सिंह के 15 साल की वादाखिलाफ़ी, मोदी के साढ़े 9 साल के कुशासन और जुमला पत्र पर भाजपाई कब बात करेंगे? जब केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को बोनस देने में प्रतिबंध लगाया, यह कहा कि एमएसपी के अतिरिक्त एक रुपया भी अतिरिक्त नहीं देंगे, तब भी अरूण साव मौन रहे। दलीय चाटुकारिता में अरूण साव तब भी चुप रहे जब मोदी सरकार ने अपने मित्र अडानी के कोयले का परिवहन करने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 63 हजार से अधिक ट्रेनें निरस्त कर दिए, अडानी के मुनाफे के लिए सीआईएल और एसईसीएल की कोल खदानों में खनन का कार्य मोदी के मित्रों को दबावपूर्वक दिए गए तब भी भाजपा सांसद मौन थे। हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला के अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में नो गो एरिया को संकुचित कर कोल खनन की अनुमति केंद्र की मोदी सरकार ने दी, तब भी छत्तीसगढ़ के भाजपाई छत्तीसगढ़िया हितों को दरकिनार कर मूक सहमति जताए। अब चुनाव नजदीक आते ही छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं भाजपाई।

ओपी चौधरी की पत्नी के खिलाफ शिकायत

रायपुर। कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी और उनकी पत्नी की शिकायत चुनाव आयोग से किया। शिकायत में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में हो रहे आसन्न विधानसभा चुनाव में रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 के बीजेपी प्रत्याशी ओ.पी चौधरी और उनकी पत्नी अदिति चौधरी के विरूद्ध जो कि रायगढ़ में अपने पति का चुनाव प्रचार कर रही है।अनुदेश क्रमांक-123 समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 23.01.1998 का पत्र सं. 437/6/98-पीएलएन-111 विषय जिन अधिकारियों के पति-पत्नि राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है उन अधिकारियों यात्राओं/ अवकाश पर प्रतिबंध-चूंकि अदिति चौधरी जो कि रेल्वे बिलासपुर क्षेत्र में नियमित कर्मचारी है इसके बाद भी अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर अपने पति के प्रचार में रायगढ़ आकर अपने पति का प्रचार कर रही है जो कि आदर्श आचार संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का घोर उल्लघंन है।अत: निवेदन है कि रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 के बीजेपी के प्रत्याशी ओ.पी. चौधरी और उनकी पत्नी अदिति चौधरी के विरूद्ध आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के आदेशों का खुला उल्लंघन किये जाने को लेकर समुचित कार्यवाही किया जाये और हमें उक्त कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा की जाये।

जाति जनगणना गांधी परिवार पर लागू होगी कि नहीं: रविशंकर

- राहुल कमाल की घोषणाएं करते हैं, पिछला हिसाब मांग रहा है छत्तीसगढ़

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान की गई घोषणाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि घोषणा करने में राहुल गांधी आजकल कमाल का काम करते हैं। बयान बहादुर, घोषणा बहादुर बन गए हैं। सिर्फ घोषणा भर तो करना है। उस घोषणा पर करना तो कुछ है नहीं तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है। राहुल गांधी पहले यह जवाब दें कि राजस्थान में उन्होंने क्या कहा था? सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में यह फैसला होगा, वह फैसला होगा। क्या हुआ? कर्नाटक के प्रचार में क्या बिजली और क्या बाकी सब, जो बातें कही थीं, बेरोजगारों के लिए रोजगार योजना पहली कैबिनेट में होगी। क्या हुआ?

पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी घोषणा करने के पहले बताएं कि छत्तीसगढ़ में पुरानी घोषणा का क्या हुआ? कुछ भी बोलते हैं। आपने कहा था 200 फूड पार्क खुलेंगे। खुले क्या? छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश बंद हो गया है। क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार नहीं, भूपेश बघेल की अगुवाई में लूट की सरकार है। ऐसे में भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे तो पहले यह बताएं पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला क्यों हुआ है? पीएससी अध्यक्ष के बेटे बहू, कांग्रेस नेताओं के परिवार के लोग, अफसरों के परिवार के लोग सलेक्ट और काबिल युवा रिजेक्ट! अब तेंदूपत्ता की घोषणा पर क्या कहा जाए? 4000 की प्रोत्साहन राशि देने कहा है। जबकि भाजपा की सरकार 4000 से 6000 बोनस दिया करती थी। पूरे तेंदूपत्ता की खरीदी से आदिवासियों को फायदा होता था। इन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं हुआ? मुझे बताया गया है कि एक आदिवासी माता तेंदूपत्ते लेकर जा रही थीं, उनका अपहरण हुआ है। यह आपकी जो स्थिति है, नई-नई घोषणाओं की बात करते हैं। पुरानी घोषणाओं का छत्तीसगढ़ हिसाब मांग रहा है। वह तो दीजिए। राहुल गांधी आदिवासियों की बात करते हैं। देश की पहली योग्य महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भाजपा ने बनाई। आप दलित के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमने योग्य गरीबों में दलित नेता रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया।पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राहुल जी आप तो कम से कम जाति जनगणना की बात न करें।

कांग्रेस सरकार आने पर जातिगत जनगणना करायेंगे: अविजीत

रायपुर। एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अविजीत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुये कहा कि बहुत ही बड़ा मुद्दा लेकर आया हूँ, यह चुनाव हम जीतने वाले है 75 पार करेंगे। यह जमीन की आवाज है लोगो की पुकार है आवाम की मर्जी है सच्चाई है हकीकत है और जो सर्वेक्षण है वो भी इस बात का पुष्टी कर रहा है। जो प्रचण्ड बहुमत आने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में ये जनसेवा में समर्पित थी और रहेगी। ये प्रतिबद्ध है निष्ठावान है कर्मठ है सुदृढ़ है मजबूत है। जो कार्य है बहुत सारे

काम हो चुके है और जो अधुरा कार्य है वो उसको अपने अंजाम और मंजील तक ले जायेगी। हमने जो वादे किये थे बहुत सारे पुरे हुये है चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या शिक्षा, धान, सब्सिडी, किसान का धान या एमएसपी का मामला हो हम जनसेवा में जनकल्याण में समर्पित थे। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के लोंगों का जो प्रतिष्ठा दी है। जो सम्मान दिया है। कांग्रेस सरकार ने सभी क्षित्रों में काम किया है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति उसके लिये सरकार ने कार्य किये। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की खान-पान, रहन-सहन और गरिमा को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। तो लोग गर्व से कहते हम छत्तीसगढ़ से है। जब आदिवासी नृत्य उत्सव हुआ तो मैं वहां उपस्थित था, बहुत खुबसूरत दृश्य देखने का मिला। कांग्रेस सरकार अपना वायदा पूरा करती है। विपक्ष की बात करें तो ना उनके पास नीति है, न ही मुद्दे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.